



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यलय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अभनपुर

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Abhanpur)

मोन्टफोर्ट आर.एस.एस. बिल्डिंग, एन.एच.30, झांकी, अभनपुर, जिला-रायपुर-493661 (छ.ग.)

(Montfort, RHS Building, NH-30, Jhanki, Abhanpur, Dist-Raipur-493661 (C.G.))

दूरभाष/Phone: - 0771-3134656, 8959931733, Email: pludhamtari@nhai.org; pluabhanpur@gmail.com



PD/DMT/Rai-Vish/Forest/8002

Date:- 07.09.2024

To

The Divisional Forest Officer (DFO)
Dhamtari,
Dist-Dhamtari (C.G.)

Sub:- Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661) Online Proposal No: - FP/CG/ROAD/119866/2021 - Compliance of observations raised by Forest Department for Stage-2 clearance - Reg.

Ref: -(i) DFO Dhamtari letter No.6274 dt.08.11.2023

(ii) This office letter No.6407 dt.11.09.2023

Sir

This has reference to PIU letter No.6407 dt.11.09.2023 wherein compliance of conditions of stage-1 clearance was submitted to DFO Dhamtari, Forest Department Govt of Chhattisgarh for necessary action for stage-2 clearance. DFO Dhamtari vide letter dt.08.11.2023 has raised certain observations for compliance.

2. Accordingly, please find enclosed compliance of observations raised by DFO Dhamtari along with relevant documents & 03 nos of undertaking.

3. It is requested to kindly take necessary action for onward processing of Stage-2 clearance of the subject project.

Encl: - As above

Project Director

Copy to:-

- (i) APCCF (Land Management), Aranya Bhawan, Naya Raipur (C.G.) - for kind information please.
- (ii) DFO Kanker & Keshkal - for kind information please.

Copy also to:-

- (i) Regional Officer (Chhattisgarh), NHAI-Raipur - for kind information please.

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, दूरभाष : 011-25074100/200

HQ : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi- 110075, Telephone No. 011-25074100/200

शर्त क्र.	प्रकरण में अधिरोपित शर्त का विवरण	वनमण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा प्रेषित टिप्पणी	अभियुक्ति
1.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / FC-III/ROCH-04/2022/678 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन		
(iv)	NPV:	वनमंडलाधिकारी कांकेर एव केशकाल	वनमंडलाधिकारी धमतरी द्वारा संशोधित
a.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at present rate for the 228.0425 ha (180.1675 ha at present and 47.875 ha after ESZ notification) forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2005 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC (PL II) dated 18/09/2003, as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	वनमंडल द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि का पुनरीक्षित गणना कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। पुनरीक्षित गणना अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्र/मा.वि./व.सं.अ./29/जी/6213 दिनांक 06.11.2023 द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि रुपये 13,90,76,776/- कैम्पा खाता में जमा करने हेतु आपको मांग पत्र जारी किया गया है। उक्त राशि कैम्पा खाता में जमा कर रसीद की प्रति इस कार्यालय में पालन के साथ प्रस्तुत करें।	मांग पत्र 7397 दिनांक 20.06.2024 के गणना अनुसार शुद्ध प्रत्याशा के अंतर की राशि रु. 31,21,247/- एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि रु.13,29,38,101/ कुल राशि रु. 13,60,59,348/- कैम्पा फण्ड में UTR संख्या CNRBR52 024090788268938 द्वारा दिनांक 07.09.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)
(xiv)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न FRA प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के FRA प्रमाण पत्र के तहत धमतरी जिला हेतु "Form- I" तथा कांकेर जिला हेतु "प्रदर्श-स" ही संलग्न किया गया है। कलेक्टर जिला कोण्डागांव द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र अनुसार कांकेर जिला हेतु "Form- I" एवं धमतरी जिला हेतु "प्रदर्श-स" संलग्न करें।	FRA प्रमाण पत्र के तहत धमतरी जिला हेतु "प्रदर्श-स" एवं कांकेर जिला हेतु "Form- I" संलग्न कर प्रेषित हैं।
(xix)	NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit	आपके द्वारा पूर्व में धमतरी जिला अंतर्गत कलेक्टर जिला- धमतरी द्वारा प्रकरण अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में स्थित 3556 (2980+353+223) वृक्षों के कटाई की दी गई अनुमति के शर्त 3 के पालन हेतु 10	भा.रा.रा.प्रा. के रियायतकार द्वारा 50,000 पौधों की नर्सरी तैयार की गई है, जिसके तहत वर्षा ऋतु में वन विभाग (वनमंडलाधिकारी, धमतरी) द्वारा चिन्हीत स्थान पर 25,000 पौधों का रोपण किया

[Signature]

[Signature]
PROJECT DIRECTOR
CHHATTISGARH (C.G.)

शर्त क्र.	प्रकरण में अधिरोपित शर्त का विवरण	वनमण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा प्रेषित टिप्पणी	अभियुक्ति
	bearing, medicinal, ornamental and indigenous/ local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	<p>गुणा वृक्षारोपण मार्ग के ROW के दोनों किनारे में किये जाने हेतु लेख किया गया है। आपके द्वारा उक्त शर्त के अनुक्रम में नर्सरी में तैयार किये जाने वाले 50,000 पौधों के 50% अर्थात् 25,000 पौधों में से 16,000 पौधें पुनः उसी क्षेत्र में लगाये जाने का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि मान्य योग्य नहीं है।</p> <p>शर्त अनुसार नर्सरी में 50,000 पौधों की तैयारी आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा या वन विभाग द्वारा किया जावेगा, इस बाबत स्पष्ट टीप देवें।</p> <p>यदि आवेदक विभाग द्वारा नर्सरी विकसित किया जावेगा तो इस बाबत वचन पत्र संलग्न करें कि पौधा तैयारी कार्य आगामी वर्षा ऋतु तक पूर्ण कर किया जावेगा तथा उनमें से 50% पौधों का वितरण आस- पास के ग्रामीणों को किया जावेगा तथा शेष 50% पौधा परियोजना स्थल के समीप वन विभाग के बतलाए स्थान पर लगाया जावेगा।</p> <p>यदि नर्सरी में पौधा तैयारी वन विभाग द्वारा कराया जाना हो तो इस बाबत प्राक्कलन एवं वांछित राशि के सम्बन्ध में वनमंडलाधिकारी धमतरी से पत्राचार करें।</p>	जायेगा तथा शेष 25,000 पौधों का वितरण आस-पास के ग्रामीणों में किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न कर प्रेषित हैं।
2.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/1083 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन		
(b)	In lieu of the translocation, block plantation of 10 times of trees felled in RoW beyond 30m will be carried out in the nearby area/ Divisions identified by Forest Department. The block plantation will consist particularly of the slow-growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa. The plantations will be facilitated by drip-irrigation and intensive care to ensure their survival.	<p>मार्ग के RoW में 30मी.के बाहर प्रभावित वृक्षों के विदोहन के एवज में शर्त अनुसार slow- growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa प्रजाति के 10 गुणा सिंचित ब्लॉक वृक्षारोपण के संबंध में कांकेर एवं केशकाल वनमंडल से मार्ग के RoW में 0-30मी. तथा 30-45 मी. में प्रभावित/विदोहित वृक्षों की जानकारी अप्राप्त है। उक्त जानकारी कांकेर एवं कोण्डागांव वनमंडल से प्राप्त होते ही 10 गुणा slow- growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa प्रजाति के सिंचित ब्लॉक</p>	मार्ग के RoW में 30 मीटर के बाहर प्रभावित वृक्षों के विदोहन के एवज में 10 गुणा ब्लॉक वृक्षारोपण की शर्त को विलोपित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7470 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध करने हेतु वनमंडलाधिकारी, धमतरी को लेख किया गया था। उक्त प्रस्ताव को छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वनमहानिरीक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर को

Gur

Project Director
PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Dhamtari (C.G.)

शर्त क्र.	प्रकरण में अधिरोपित शर्त का विवरण	वनमण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा प्रेषित टिप्पणी	अभियुक्ति
	Henceforth, the plantation will be raised by the Forest Department instead of the NHAI to ensure better success. All costs including maintenance will be borne by the User Agency and in every six month a report will be submitted to the Regional Office of MoEF & CC, Raipur;	वृक्षारोपण हेतु मांग पत्र जारी किया जावेगा। वर्तमान में पालन प्रतिवेदन के साथ आवेदक विभाग शर्त अनुसार 10 गुणा slow- growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa प्रजाति के सिंचित ब्लॉक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा मांग की जाने वाली वांछित राशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्ध है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न किया जावे।	आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। वर्तमान में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से MOEF&CC नई दिल्ली से उक्त संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जो कि अपेक्षित है। उक्त प्रकरण पर जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य होगा। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
(c)	Avenue plantations of 10 times of trees felled in 30m RoW will be raised by the User agencies at their own cost.	शर्त क्रमांक (xix) के पालन की पुनरावृत्ति की गई है, जो कि मान्य योग्य नहीं है। मार्ग के RoW में 30मी. के अन्तर्गत प्रभावित वृक्षों के विदोहन के एवज में शर्त अनुसार 10 गुणा ऐवेन्यू वृक्षारोपण आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा, इस बाबत स्पष्ट टीप देवें। यदि आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा तो इस संबंध में वचन पत्र संलग्न किया जावें। यदि 10 गुणा ऐवेन्यू वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा कराया जाना हो तो इस बाबत प्राक्कलन एवं वांछित राशि के संबंध में वनमंडलाधिकारी धमतरी से पत्राचार करें। 10 गुणा ऐवेन्यू वृक्षारोपण हेतु लगाये जाने वाले पौधों की संख्या कांकर एवं केशकाल वनमंडल से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत पृथक से प्रेषित किया जावेगा।	मार्ग के RoW में 30मी. के अन्तर्गत प्रभावित वृक्षों के विदोहन के एवज में 10 गुणा ब्लॉक वृक्षारोपण की शर्त को विलोपित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7470 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध करने हेतु वनमंडलाधिकारी, धमतरी को लेख किया गया था। उक्त प्रस्ताव को छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वनमहानिरीक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। वर्तमान में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से MOEF&CC नई दिल्ली से उक्त संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जो कि अपेक्षित है। उक्त प्रकरण पर जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य होगा। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।

G

Project Director
PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Dhamtari (C.G.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अभनपुर

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Abhanpur)

मोन्टफोर्ट आर.एच.एस. बिल्डिंग, एन.एच.30, झांकी, अभनपुर, जिला-रायपुर-493661 (छ.ग.)

(Montfort, RHS Building, NH-30, Jhanki, Abhanpur, Dist-Raipur-493661 (C.G.))

दूरभाष/Phone: - 0771-3134656, 8959931733, Email: piudhamtari@nhai.org; piuabhanpur@gmail.com



Ref:-Stage-1 Stipulated conditions issued vide letter No.FC/iii/IROCH-04/2022/673 dt.12.04.2022

Condition:(xix):- NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost.

A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.

UNDERTAKING

User Agency, hereby undertake for the project "Development of Economic Corridors, Inter-Corridors, Feeder Routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0+000 to Ch.124+661) in the state of Chhattisgarh" that the NHAI through Concessionaire has established separate nursery for 50,000 seedlings & plantation of 50% seedlings (25,000) will be done at the places identified by the DFO Dhamtari & remaining 50% seedlings (25,000) will be voluntary distributed free of cost to the local community residing in the vicinity of project road.

Date: - 07.09.2024

Project Director

Name: - Pankaj Ojha


PROJECT DIRECTOR
NHAI, P. U. Dhamtari (C.G.)
Seal & Signature



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अभनपुर

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Abhanpur)

मोन्टफोर्ट आरएचएस बिल्डिंग, एन.एच.30, झांकी, अभनपुर, जिला-रायपुर-493661 (छ.ग.)

(Montfort, RHS Building, NH-30, Jhanki, Abhanpur, Dist-Raipur-493661 (C.G.)

दूरभाष/Phone: - 0771-3134656, 8959931733, Email: pludhamtar1@nhai.org; plubabhanpur@gmail.com



Ref:-Compliance of additional condition stipulated conditions in IRO-Raipur letter no.FC-III1IROCH-04/2022/1083 dated 02.12.2022.

Condition-B :- In lieu of the translocation block plantation of 10 times of trees felled in RoW beyond 30 m will be carried out in the nearby area/Divisions identified by Forest Department. The block plantation will consist particularly of the slow-growing trees Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa. The plantations will be facilitated by drip irrigation and intensive care to ensure their survival. Henceforth, the plantations will be raised by the Forest Department instead of the NHAI to ensure better success. All cost including maintenance will be borne by the User agency and in every six month a report will be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Raipur

UNDERTAKING

User Agency, hereby undertake for the project "Development of Economic Corridors, Inter-Corridors, Feeder Routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0+000 to Ch.124+661) in the state of Chhattisgarh" that user agency will abide by the decision of MoEF&CC on the request made by NHAI for waiving of the aforesaid condition.

Date: - 07.09.2024

Project Director

Name: - Pankaj Ojha

Seal & Signature
PROJECT DIRECTOR
RAIPUR DIVISION (C.G.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, अभनपुर

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Abhanpur)

मोन्टफोर्ट आर.एच.एस. बिल्डिंग, एन.एच.30, झांकी, अभनपुर, जिला-रायपुर-493661 (छ.ग.)

(Montfort, RHS Building, NH-30, Jhanki, Abhanpur, Dist-Raipur-493661 (C.G.))

दूरभाष/Phone: - 0771-3134656, 8959931733, Email: piudhamtari@nhaa.org; piuaabhanpur@gmail.com



Ref:-Compliance of additional condition stipulated conditions in IRO-Raipur letter no.FC-III/IROCH-04/2022/1083 dated 02-12-2022.

Condition-C :- Avenue plantations of 10 times of trees felled in 30m RoW will be raised by the User agencies at their own cost.

UNDERTAKING

User Agency, hereby undertake for the project "Development of Economic Corridors, Inter-Corridors, Feeder Routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0+000 to Ch.124+661) in the state of Chhattisgarh" that user agency will abide the decision of MoEF&CC on the request made by NHA for waiving of the aforesaid condition.

Date: - 07.09.2024

Project Director

Name: - Pankaj Ojha

Seal & Signature

PROJECT DIRECTOR
PIU Abhanpur (C.G.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, अमनपुर

(Office of Project Director, Project Implementation Unit, Abhanpur)

मोन्टफोर्ट आर.एच.एस. बिल्डिंग, एन.एच.30, झांकी, अमनपुर, जिला-रायपुर-493661 (छ.ग.)

(Montfort, RHS Building, NH-30, Jhanki, Abhanpur, Dist-Raipur-493661 (C.G.))

दूरभाष/Phone: - 0771-3134656, 8959931733, Email: piudhamtari@nha.org; piuabhanpur@gmail.com



PD/DMT/Rai-Vish/Forest/8001

Dated 07.09.2024

To,

The Divisional Forest Officer (DFO)
Dhamtari, Dist-Dhamtari

Sub:- Diversion of 228.0425 Hac. of Forest land in favour of NHA PIU Dhamtari for Development of Economic Corridors, Inter-Corridors, feeder routes & coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Visakhapatnam (Ch.0.000 to Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana (Forest Proposal is for between Km.42+844 to Km.124.661) - Revised Demand note for deposition of balance amount against Compensatory afforestation & NPV value - Reg.

Ref:- DFO Dhamtari letter No.3397 dt.20.06.2024

Sir,

This has reference to DFO Dhamtari letter dt.20.06.2024 vide which revised demand note towards additional amount for Compensatory afforestation & NPV amounting to Rs.13,60,59,348/- (Rs.31,21,247 for NPV+Rs.13,29,38,101/- for CA) has been forwarded to this office for payment in CAMPA fund as per the directions conveyed in FRCM meeting dt.22.05.2024 towards diversion of 228.0425 Ha. Of land for the subject project.

2. The details of additional amount as per demand note submitted by DFO Dhamtari are under :-

Sr. No.	Description	Forest Division	Amount to be deposited	Amount earlier deposited	Difference amount to be deposited
1	Compensatory afforestation (para-iii)	Dhamtari, Kanker & Keshkal	457 Ha.x11,69,680/- = 53,45,43,760/- (Rs.11,69,680/- per Ha. as per the rate for Irrigated Plantation for FY 2024-25)	40,16,05,659/- (Rs.8,78,787/- as per the rate for 2022-23)	13,29,38,101/-
2	NPV (para iv(a))	Dhamtari (147.6694 Ha)	18,67,47,817/-	18,67,47,817/-	0
		Kanker (39.0869 Ha.)	5,29,44,553/-	5,29,44,553/-	0
		Keshkal (41.2862 Ha.)	5,89,95,597/-	5,58,74,350/-	31,21,247/-
		Total :-			13,60,59,348/-

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, दूरभाष : 011-25074100/200
HQ : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi- 110075, Telephone No. 011-25074100/200

3. As approved by Competent Authority NHAI, an additional amount of Rs.13,60,59,348/- as sought by DFO Dhamtari has been deposited in CAMPA fund through UTR No.CNRBR52024090788268938 dt.07.09.2024 by F&A unit NHAI RO-Raipur & same has been uploaded on parivesh portal.

4. This is for your information & further necessary action in the matter please.


07/09/24
Project Director

Copy to:-

1. Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Aranya Bhawan, Naya Raipur - for kind information & necessary action please.
2. PCCF (Forest), Govt of Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Naya Raipur - for kind information please.
3. APCCF (Land Management), Aranya Bhawan, Naya Raipur - for kind information please.
4. DFO Kaner & Keshkal - for kind information please.

Copy also to:-

1. CGM (Tech) cum Regional Officer-Chhattisgarh, NHAI, Raipur-for kind information, please.
2. Dr.Biswajit Mukhopadhyay, Advisor, Environment Division, NHAI-HQ - for kind information & necessary action, please.
3. Joint Advisor (Env./P), RO-Raipur - for kind information please.



कार्यालय कलेक्टर

(आदिवासी विकास) जिला-धमतरी (छ०ग०)

E-mail. tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone no. 07722-232142, Fax no. 07722-232143

प्रमाणित ५३ / आदि०वि० / वन अधि० / न०क०- / 2022-23, धमतरी, दिनांक ०२/०४/२०२४
प्रति,

परियोजना निदेशक,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ब्लाक एफ-5 शिवराज ग्रीन्स सिहावा रोड धमतरी

जिला धमतरी ।

विषय :- भारतमला परियोजना के तहत प्रदर्श स जारी करने बाबत ।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्रमांक/
11.01.2024 कार्यालय को प्राप्त आवेदन दिनांक 01 अप्रैल 2024

--- 000 ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा भारतमला परियोजना के तहत ग्राम सरगी- झांझरकेरा- केकराखोली को 54.7859 हे. तथा ग्राम राजपुर- डोकाल- झुरातराई- कौहाबाहरा- खैरभरी-करैहा-चिंवर्री को 92.8835 हे. का प्रदर्श स मांग की गई है । पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3072 दिनांक 21.07.2022 एवं पत्र क्रमांक/3070 दिनांक 21.07.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है ।

अतः आपके मांग के आधार पर ग्राम सरगी-झांझरकेरा-केकराखोली को 54.7859 हे. तथा ग्राम राजपुर-डोकाल-झुरातराई-कौहाबाहरा-खैरभरी-करैहा-चिंवर्री को 92.8835 हे. का प्रदर्श स पृथक-पृथक हस्ताक्षर उपरांत संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास धमतरी

पृ०क्रमांक/५५/आदि०वि०/वन अधि०/न०क०- /2022-23, धमतरी, दिनांक ०२/०४/२०२४
प्रतिलिपि -

01. कलेक्टर महोदय जिला-धमतरी छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

02. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल धमतरी की ओर सूचनार्थ ।

03. अधीक्षक भू-अभिलेख धमतरी को सूचनार्थ ।

04. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अध्यक्ष अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कुरुद/नगरी को सूचनार्थ ।

05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोड/ नगरी को सूचनार्थ ।

06. संवर्धित ग्राम सभा.....को सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास धमतरी

प्रदर्श- रा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम् (छ ग उडीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील नगरी में स्थित ग्राम डोकाल, कोटरवाही, पालगांव, वेधवापथरा, खैरभरी, करैहा, सारंगपुरी, चिवरी, चिवरीमाल, कुकरीकोना व सांकरा में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल वन भूमि 92.8835 हे के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वन भूमि 92.8835 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम डोकाल, कोटरवाही, पालगांव, वेधवापथरा, खैरभरी, करैहा, सारंगपुरी, चिवरी, चिवरीमाल, कुकरीकोना व सांकरा तहसील नगरी में स्थित है, में तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक के आधार पर अनुभाग स्तरीय वनअधिकार समिति नगरी की बैठक दिनांक 27.05.2022 के आधार पर प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा बैठक में किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
01	डोकाल, कोटरवाही, पालगांव, वेधवापथरा, खैरभरी, करैहा, सारंगपुरी, चिवरी, चिवरीमाल, कुकरीकोना व सांकरा	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर अनुभाग स्तरीय वनअधिकार समिति नगरी की बैठक दिनांक 27.05.2022 के आधार पर प्रदाय किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (2) अन्तर्गत शारान द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलेक्टर

जिला- धमतरी (छ०ग०)

प्रदर्श- स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम् (छ.ग उडीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील कुरुद (मगरलोड) में स्थित ग्राम सरगी, झाझरकेरा व केकराखोली में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल वन भूमि 54.7859 हे. के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वन भूमि 54.7859 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सरगी, झाझरकेरा व केकराखोली तहसील कुरुद (मगरलोड) में स्थित है, में तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक के आधार पर अनुभाग स्तरीय वनअधिकार समिति नगरी की बैठक दिनांक 14.07.2022 के आधार पर प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा बैठक में किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धाराकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
01	सरगी, झाझरकेरा व केकराखोली	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर अनुभाग स्तरीय वनअधिकार समिति कुरुद (मगरलोड) की बैठक दिनांक 14.07.2022 के आधार पर प्रदाय किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलेक्टर

जिला- धमतरी (छ०ग०)

फाइल - 1

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांगेर

—ज्ञापन—

क्रमांक 471/भू.अभि./अ.भू.अ./2024
प्रति,

कांगेर, दिनांक 15/4 /2024

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कार्यालय परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई धमतरी

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।


संदर्भ:- आपका पत्र क्र./पनि/पकाई/धमतरी/राय-विशा/फॉरेस्ट/6899 दिनांक 11/01/2024

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा रायपुर-विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 अंतर्गत परियोजना में आने वाले ग्रामों जामगांव, डब्बीपानी, शामतरा, बिहावापारा, सारवण्डी एवं बासनवाही हेतु "Form-I" प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु लेख किया गया है।

अतः ग्राम सभा में पारित संकल्पों के आधार पर ग्राम जामगांव, डब्बीपानी, शामतरा, बिहावापारा, सारवण्डी एवं ग्राम बासनवाही में कलेक्टर द्वारा जारी "प्रदर्श-स" प्रमाण पत्र के अनुसार Annexure-1 (Form-1) प्रमाण प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- Annexure-1 (Form-1) प्रमाण प्रमाण पत्र।


अपर कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांगेर

Annexure-I

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. 112(1)

Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **17.3451 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Jamgaon villages(S)** in **Narharpur Tehsils**.

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **17.3451** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.




(Dr. Prishanka Shukla)
Collector

District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Annexure-I

**Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)**

No. 117 (1)

Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **18.6283 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Basanvahi** villages(S) in **Sarona Tehsils**.


This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **18.6283** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.




(Dr. Priyanka Shukla)
Collector

 District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. 116(1)Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **2.1028 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Salhetola villages(S) in Sarona Tehsils.**

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.1028** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.



(Dr. Priyanka Shukla)
 Collector

District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. 115 (1)Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **2.9270 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Achhidongari villages(S) in Sarona Tehsils.**

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.9270** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to S.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.




(Dr. Priyanka Shukla)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. 114(C1)Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **3.7082 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Shamtara villages(S) in Sarona Tehsils.**

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.7082** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.



(Dr. Priyanka Shukla)
 Collector

District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Annexure-I

**Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)**

No. 113(1)

Date 18-11-2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **15.326 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **National Highways Authority of India** in Uttar Bastar Kanker district for **Construction of Road** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Dabbipani** villages(S) in **Sarona Tehsils**.

This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **15.326** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to S.

(b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.




(Dr. Priyanka Shukla)
Collector

District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

✉ cwlwgc@gmail.com, apccfwildlife@gmail.com

(☎0771-2512880, ☎ 0771-2512853)

// आदेश //

आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-2-546/110

नवा रायपुर, दिनांक 02/05/2024

छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) इकोनामिक कॉरिडोर निर्माण हेतु मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रायपुर वृत्त रायपुर का पत्र क./तक.शा./रा./4199 दिनांक 23.04.2024 एवं पत्र क. 7827 दिनांक 23.08.2021, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर का पत्र क. 2720 दिनांक 19.08.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कांकेर वृत्त कांकेर का पत्र क./2021/2615 दिनांक 17.08.2021 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क. 10-3/2020 IA, III Govt. of India MoEF&CC दिनांक 02.03.2020 में जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क. ((A) Project sepcific condition (I), (II) & (III) में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आवेदनकर्ता परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धमतरी वनमण्डल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वनमण्डल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वनमण्डल अंतर्गत 39.0869 हे. इस प्रकार कुल 228.0425 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग के लिए वन्यप्राणी संरक्षण योजना संबंधित वनमण्डलाधिकारी तथा मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रायपुर वृत्त रायपुर, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर तथा मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कांकेर वृत्त कांकेर द्वारा उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व का डिफाल्ट ईएसजेड एरिया में आने के कारण प्रकरण में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सहमति प्राप्त कर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वाईल्ड लाइफ डिबीजन) नई दिल्ली का पत्र क. 6-112/2022 डब्ल्यू एल दिनांक 03.07.2023 द्वारा एनीमल पैसेज प्लॉन को भारतीय वन्यजीव संस्थान से परीक्षण कराये जाने सहित अन्य 8 शर्तों को अधिरोपित करते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। **परिशिष्ट-1**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा एनीमल पैसेज प्लॉन को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को प्रेषित किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा एनीमल पैसेज प्लॉन का परीक्षण करते हुए आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वन्यप्राणी पैसेज के साइट सलेक्शन (The site selection of mitigation measures are appropriate) को सही पाया जाना उल्लेखित है। इन्द्रावती और उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कॉरिडोर क्षेत्र अंतर्गत 6.54 कि.मी. का वनक्षेत्र आता है जिसके लिए मिटिगेशन मेजर के रूप में 3 Viaducts और 1 Twin tube tunnel प्रस्तावित किया गया है जिसकी कुल लंबाई 3.79 कि.मी. है, शेष बचे वन क्षेत्र के 2.75 कि.मी. लंबाई में वन्यप्राणियों के सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने हेतु फेन्सिंग किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है। यह कार्य आवेदक संस्था द्वारा पूर्ण कराया जावेगा। **परिशिष्ट-1**

प्रस्तुत वन्यप्राणी संरक्षण योजना का परीक्षण किया गया। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत वन्यप्राणी संरक्षण योजना का परीक्षण पश्चात अन्य घटकों को समाहित करते हुए कुल 10 वर्षों में घटकवार राशि का उपयोग करते हुए वर्षवार आबंटन किया जाता है। अनुमोदित योजना में मुख्य रूप से जलस्रोत का विकास, मृदा जल संरक्षण, अखाद्य खरपतवार का उन्मूलन, चारागाह विकास, फलदार वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा, हाथी मित्रदल और संयुक्त वन प्रबंधन समिति का सुदृढीकरण, साइनेज एवं होर्डिंग्स, जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन आदि घटकों में बजट प्रावधान किया गया है जिसका वनमण्डलवार विवरण **परिशिष्ट-2** में दर्शित है। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं का पालन आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा।

उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना की कुल लागत राशि **रूपये 1209.80 लाख** (धमतरी वनमण्डल राशि **रु. 711.85 लाख**, कांकेर वनमण्डल राशि **रु. 178.825 लाख**, केशकाल वनमण्डल राशि **रु. 218.50 लाख** तथा उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व राशि **रु. 100.625 लाख**) वर्तमान दरों पर है। परियोजना में देरी होने से समय लागत बढ़ेगी, जिसमें प्राईस इन्डेक्स के हिसाब से वृद्धि होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो भी लागत आयेगी वह प्रस्तावकों को वन विभाग में एकमुश्त जमा करानी होगी, जिससे मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। स्वीकृत वन्यप्राणी संरक्षण योजना अनुसार वन विभाग को प्राप्त राशि को कैम्पा के एपीओ में सम्मिलित करने के पूर्व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक से अनुमोदन लिया जायेगा। वन विभाग इस प्रकार जमा की गई राशि से वन्यप्राणी संरक्षण योजना में दर्शाये समय सारणी के अनुसार क्रियान्वित करेगा।

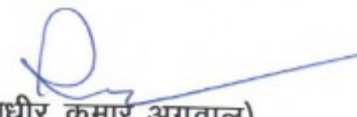
अनुमोदित वन्यप्राणी योजना में दर्शाये गये उपरोक्त घटकों के संगत फील्ड में किये जाने वाले कार्यों का कार्यवार/स्थलवार प्रोजेक्ट संबंधित वनमण्डलाधिकारी के द्वारा तत्समय प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धांतों (व्यय नार्मस, कार्य की प्रकृति, वन्यप्राणी प्रबंधन के संबंध में लागू होने वाले अन्य तकनीकी तथ्यों व निर्देशों) के अनुरूप तैयार कर सक्षमतानुसार तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन हेतु अनुशंसा सहित संबंधित मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी को प्रेषित किया जावेगा। संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रोजेक्ट की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन की अनुशंसा के साथ मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा। प्रोजेक्ट का परीक्षण वन्यप्राणी प्रबंधन की उपयुक्तता की दृष्टि से किया जाकर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के द्वारा कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रोजेक्ट, प्रशासकीय स्वीकृति/बजट आबंटन करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के पश्चात ही कार्यों का क्रियान्वयन व.मं.अ. द्वारा किया जावेगा।

वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. द्वारा किया जावेगा। किये जा रहे कार्यों की भौतिक व आर्थिक प्रगति से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रतिमाह व.मं.अ. द्वारा अवगत कराया जावेगा। आवेदक संस्थान वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कुल राशि **रूपये 1209.80 लाख** (अक्षरी बारह करोड़ नौ लाख अस्सी हजार मात्र) एकमुश्त जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार **परिशिष्ट-1 एवं 2.**

Annexure - 1 पृ. 1 & 5

Annexure 2 - पृ. 1 & 15

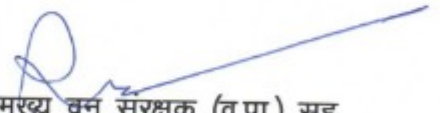

(सुधीर कुमार अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-2-546/1974

नवा रायपुर, दिनांक 02/05/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।
3. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रायपुर वृत्त रायपुर ।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कांकेर वृत्त कांकेर ।
5. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन एवं क्षेत्रीय निदेशक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर ।
6. वनमण्डलाधिकारी, धमतरी/कांकेर/केशकाल वनमण्डल ।
7. उप निदेशक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद
8. महाप्रबंधक (तक.) सह परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा. इकाई धमतरी ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

F.No.6-112/2022 WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

Date: 3rd July, 2023

To
The Principal Secretary,
Forest Department, Aranya Bhawan,
Medical Collage Road,
Fafadih, Raipur 492001.

Sub: Proposal for use of 198.3084 of forest land from Udanti-Sitanadi Tiger Reserve for development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under BharatmalaPariyojana-FP/CG/ROAD/119866/2021.

Sir,

Reference is invited to the subject mentioned above. The above proposal was discussed in the 72nd Meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life held on 25th April, 2023 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.

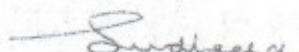
2. After discussion, the standing committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The animal passage plan needs to be examined by the WII.
2. The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only.
3. Any other condition imposed from time to time by forest department.
4. There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.
5. All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/cc culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals.
6. Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.
7. There will not be a right of passage to the public via the underpass.
8. The Chief Wild Life Warden should have an adequate monitoring mechanism in place.
9. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.

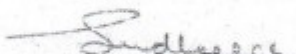
4. The Director, Wildlife Institute of India, Dehradun was requested by the Ministry for examination of the animal passage plan who based on the field inspections carried out by Wildlife Institute of India has submitted the report (enclosed) for your information and compliance.

Yours faithfully,


(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in

Copy to:

1. Chief Wild Life Warden, Forest Department, Aranya Bhawaan, Medical Collage Road, Fafadih, Raipur-492001.
2. Deputy Director General of Forests, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines, Nagpur-440001 **for monitoring the compliance of conditions.**
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC.


(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in

Comments of Wildlife Institute of India on the proposed animal passage plan as part of Raipur-Vishakhapatnam greenfield highway (Ch. 0.000 – Ch. 124.661) in the state of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana

Reference: 72nd meeting of the Standing Committee of NBWL, MoM – 72.4.33 (Page 60-61)

Background:

The forested landscape in Central India represents a mosaic of protected areas and multiple use zones. Presence of source population such as Tadoba Andhari Tiger Reserve, holds the lifeline for recovery of tiger population in a much larger connected landscape that includes tiger reserves such as Navegaon-Nagzira, Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi (Figure 1); Kanger Valley National Park and wildlife sanctuaries such as Chaprala, Pamed, Bhairamgarh and Sunabeda. Outside these protected areas, managed forests of Gadchiroli, Bijapur, Dantewada, North Bastar, Kondagaon, Keshkal and Kanker provide forest connectivity. Maintaining the integrity of this landscape is of utmost importance for future recovery of tiger population in the above-mentioned protected areas as well as managed forests.

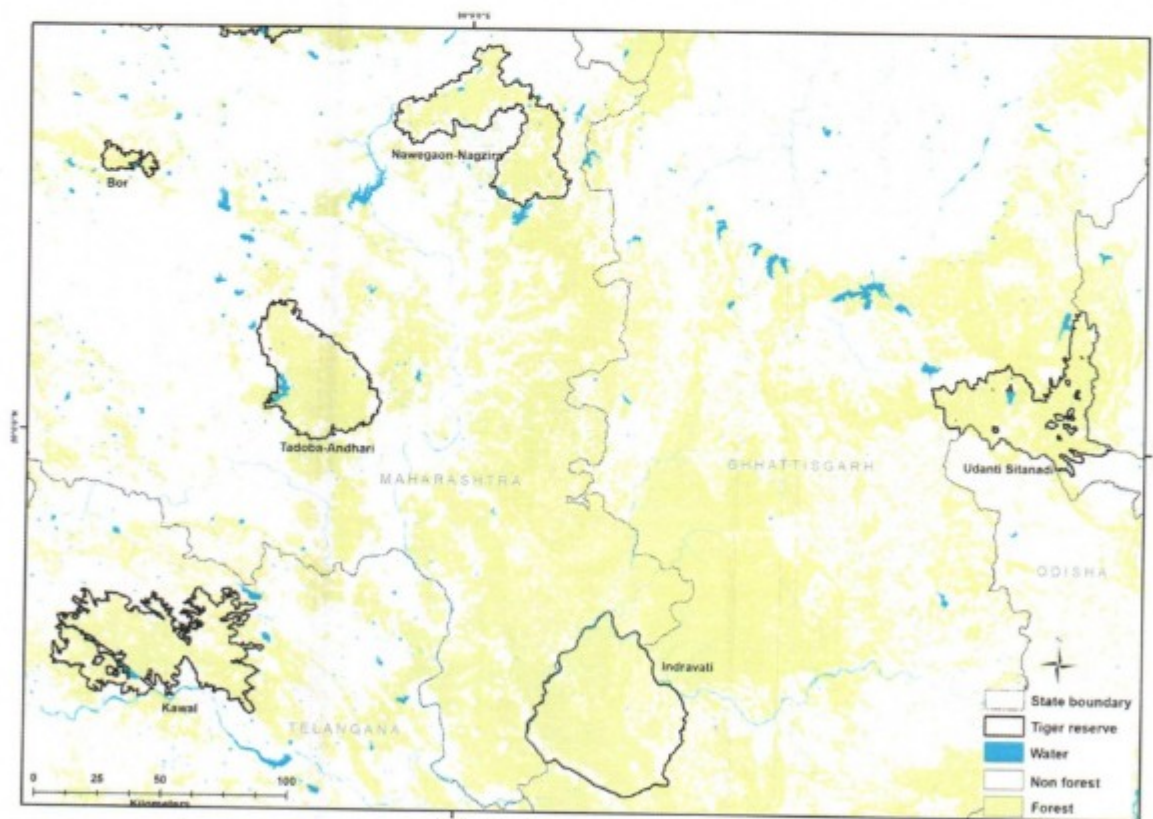


Figure 1. Thriving tiger population in Tadoba Andhari TR acts as a major lifeline for recovery of tiger population in other reserves such as Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi in Central India that still maintain forest connectivity.

The proposed road in the context of tiger reserves in Central India:

Two stretches of proposed alignment of the green field economic corridor, Raipur Vishakhapatnam under Bharatmala Pariyojana (NH130 CD) passes through the deemed ESZ boundary of 10 km of Udanti Sitanadi Tiger Reserve. The project alignment is outside the draft ESZ of 2.5 km proposed by the Government of Chhattisgarh. However, the project alignment intersects near chainage 104.900 to chainage 108.350 for a distance of 3.45 km, the tiger dispersal corridor between Indravati Tiger Reserve-Udanti Sitanadi Tiger Reserve and Sunabeda Wildlife Sanctuary delineated by NTCA and WII in 2014 (Fig. 2).



Figure 2. The least cost path corridor between Indravati and Udanti Sitanadi Tiger Reserves. The proposed road passes through this corridor within the default ESZ (10 km) and outside the proposed ESZ (2.5 km) of Udanti Sitanadi TR.

Proposed mitigation measures in the corridor:

The user agency has proposed three viaducts of length 300m at ch. 104.210 to 104.510; 300 m at ch. 105.719 to 106.019; 360 m at 106.260 to 106.620 and a twin tube tunnel of 2.79 km from ch. 106.820 to 109.610 (Fig. 3). The height of these viaducts varies from a minimum of 6m to a maximum of 8m, thus providing adequate scope for movement of large herbivores like elephants using this landscape.



Figure 3. A total of three via ducts spanning over 960m and a twin tube tunnel of 2.79 km are the proposed mitigation measures by the project proponent.

Observations based on the site inspection:

A site inspection was carried out by Dr. Bivash Pandav, Scientist G of WII on 12 and 13 June 2023. Following a detailed discussion with the engineers of NHAI, all the locations where the three viaducts and the twin tube tunnel are proposed were visited. The site selection of mitigation measures are appropriate. The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km. The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision with wild animals.

Annexure-2

Details of Financial proposal - Dhamtari Division

S.no.	Description of Item of work	Unit (No./Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
1	Improvement of water availability by digging of ponds and water holes.	L.S.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2	Soil water conservation works (LBCD, BCD, Gulley plucking, Dams)	L.S.	8.00	6.00	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	(A) Removal of invasive Alien species hindering the growth and regeneration of valuable species for wild life .	400 Ha.	6.40 80 Ha.	6.40 80 Ha.	6.40 80 Ha.	6.40 80 Ha.	6.40 80 Ha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	(B) Mopping up the same area to remove the remnants	400 Ha.		3.20 80 Ha.	3.20 80 Ha.	3.20 80 Ha.	3.20 80 Ha.	3.20 80 Ha.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
4	(A) Pasture development by removing alien species in natural grass lands and also in potential grass lands where the density of canopy <0.4	300 Ha.	12.00 60 Ha.	12.00 60 Ha.	12.00 60 Ha.	12.00 60 Ha.	12.00 60 Ha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	(B) Pasture development by Planting / sowing of palatable grass seeds/ slips	200 Ha.	16.00 50 Ha.	16.00 50 Ha.	16.00 50 Ha.	16.00 50 Ha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(C) Maintenance works of grass seed planting area for Three years	200 Ha.	0.00	1.50 50 Ha.	3.00 100 Ha.	4.50 150 Ha.	4.50 150 Ha.	3.00 100 Ha.	1.50 50 Ha.	0.00	0.00	0.00	

S.no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
5	Improvement of stock by dressing of existing stumps of browsable species and cut back (The DFO should inspect the area and after proper marking and hammering , the dressing of live stumps can be permitted) and Gap plantation of fruit bearing trees like Aonla, Jamun, Bel, Ghular, Bargad, and Peepal by planting in 1 st year itself)	400 Ha.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
			80 Ha.	80 Ha.	80 Ha.	80 Ha.	80 Ha.						
6	Maintenance of fruit trees plantation for 5 years	400 Ha.	0.00	3.20	6.40	9.60	12.80	16.00	12.80	9.60	6.40	3.20	80.00
				80 Ha.	160 Ha	240 Ha.	320 Ha.	400 Ha.	320 Ha.	240 Ha.	160 Ha.	80 Ha.	
7	Fire protection by cleaning and maintaining the fire lines (Natural and artificial) and purchase of fire fighting equipments.	L.S.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
8	Hathi Mitra Dal & Empowerment of JFMCs, public awareness training etc. and miscellaneous works/ activities, purchase of equipments that may be developed subsequently to reduce human - animal conflicts.	L.S.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00
9	Establishment of early warning Elephant alert system	L.S	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

S.no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
10	Purchase of utility vehicle" Gajraj Vahan" for the field to transport of man, materials used in Human-Wildlife conflicts. And POL and maintenance for 5 years	L.S.	0.00	23.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	43.00
11	Biodiversity conservation, empowerment of BMC, training awareness etc	L.S.	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
12	Semi reflective Wildlife warning signages and hoardings near wildlife passes and in forest area.	L.S.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
13	Monitoring and evaluation of works	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
	Total		102.40	114.30	100.00	100.70	87.90	36.20	28.30	19.60	16.40	13.20	619.00
	+15% Escalation		15.36	17.145	15.00	15.105	13.185	5.43	4.245	2.94	2.46	1.98	92.85
	Grand Total		117.76	131.445	115.00	115.805	101.085	41.63	32.545	22.54	18.86	15.18	711.85

Details of Financial proposal - Kanker Division

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
1	Improvement of water availability by digging of ponds and water holes.	L.S.	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2	Soil water conservation works (LBCD, BCD, Gulley plucking, Dams)	L.S.	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3	(A) Pasture development by Removal of invasive Alien species hindering the growth and regeneration of valuable species for wild life .	200 Ha.	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
		50 Ha.		50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.							
	(B) Mopping up the same area to remove the remnants	200 Ha.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.						
4	Improvement of stock by dressing of existing stumps of browsable species and cut back (The DFO should inspect the area and after proper marking and hammering , the dressing of live stumps can be permitted)	200 Ha.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		40 Ha.		40 Ha.	40 Ha.	40 Ha.	40 Ha.						

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
	and Gap plantation of fruit bearing trees like Aonla, Jamun, Bel, Ghular, Bargad, and Peepal by planting in 1 st year itself)												
5	Maintenance of fruit trees plantation for 5 years	200 Ha.	0.00	1.60	3.20	4.80	6.40	8.00	6.40	4.80	3.20	1.60	40.00
				40 Ha.	80 Ha	120 Ha.	160 Ha.	200 Ha.	160 Ha.	120 Ha.	80 Ha.	40 Ha.	
6	Fire protection by cleaning and maintaining the firelines (Natural and artificial) and purchase of fire fighting equipments.	L.S.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
7	Empowerment of JFMCs, public awareness training etc. and miscellaneous works/ activities that may be developed subsequently to reduce Human - animal conflicts.	L.S.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
8	Establishment of early warning Elephant alert system	L.S.	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
9	Biodiversity conservation, empowerment of BMC, training awareness etc	L.S.	2.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
10	Semi reflective Wildlife warning signages and hoardings near wildlife passes and in forest area.	L.S.	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0
11	Monitoring and evaluation of works		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	3.50
	Total		27.00	25.60	26.20	26.80	17.40	10.00	8.40	6.30	4.70	3.10	155.50
	+15% Escalation		4.05	3.84	3.93	4.02	2.61	1.50	1.26	0.945	0.705	0.465	23.325
	Grand Total		31.05	29.44	30.13	30.82	20.01	11.50	9.66	7.245	5.405	3.565	178.825

Details of Financial proposal - Keshkal Division

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
1	Improvement of water availability by digging of ponds and water holes.	L.S.	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2	Soil water conservation works (LB CD, BCD, Gulley plucking, Dams)	L.S.	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
3	(A) Pasture development by Removal of invasive Alien species hindering the growth and regeneration of valuable species for wild life .	200 Ha.	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
		50 Ha.		50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.							
	(B) Mopping up the same area to remove the remnants	200 Ha.		2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.						
4	Improvement of stock by dressing of existing stumps of browsable species and cut back (The DFO should inspect the area and after proper marking and hammering , the dressing of live stumps can be permitted) and Gap plantation of fruit bearing trees like Aonla, Jamun, Bel, Ghular, Bargad, and Peepal by planting in 1 st year itself)	200 Ha.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		40 Ha.		40 Ha.	40 Ha.	40 Ha.	40 Ha.						
5	Maintenance of fruit trees plantation for 5 years	200 Ha.		1.60	3.20	4.80	6.40	8.00	6.40	4.80	3.20	1.60	40.00
				40 Ha.	80 Ha	120 Ha.	160 Ha.	200 Ha.	160 Ha.	120 Ha.	80 Ha.	40 Ha.	

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
6	Fire protection by cleaning and maintaining the firelines (Natural and artificial) and purchase of fire fighting equipments.	L.S.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	22.00
7	Empowerment of JFMCs, public awareness, training etc. and miscellaneous works/ activities that may be developed subsequently to reduce human - animal conflicts.	L.S.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
8	Establishment of early warning Elephant alert system	L.S.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
9	Biodiversity conservation, empowerment of BMC, training awareness etc	L.S.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
10	Semi reflective Wildlife warning signages and hoardings near wildlife passes and in forest area.	L.S.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
11	Monitoring and evaluation of works		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.00
	Total		35.00	32.60	34.20	34.80	18.40	11.00	9.40	6.80	4.70	3.10	190.00
	+15% Escalation		5.25	4.89	5.13	5.22	2.76	1.65	1.41	1.02	0.705	0.465	28.50
	Grand Total		40.25	37.49	39.33	40.02	21.16	12.65	10.81	7.82	5.405	3.565	218.50

Details of Financial proposal -Udanti-Sitanadi Tiger Reserve

S. no.	Description of Item of work	Unit (No./ Area)	Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
			1 st yr	2 nd yr	3 rd yr	4 th yr	5 th yr	6 th yr	7 th Yr	8 th Yr	9 th Yr	10 th yr	Total
1	Improvement of water availability by digging of ponds and water holes.	L.S.	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2	Soil water conservation works (LBCD, BCD, Gulley plucking, Dams)	L.S.	1.0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3	(A) Pasture development by Removal of invasive Alien species hindering the growth and regeneration of valuable species for wild life .	150 Ha.	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
		50 Ha.											
	(B) Mopping up the same area to remove the remnants	150 Ha.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				50 Ha.	50 Ha.	50 Ha.							
4	(A) Pasture development by removing alien species in natural grass lands and also in potential grass lands where the density of canopy <0.4	50 Ha.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			25 Ha.	25 Ha.									
	(B) Pasture development by Planting / sowing of palatable grass seeds/ slips	50 Ha.	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
				25 Ha.	25 Ha.								
	(C) Maintenance works of grass seed planting area for Three years	50 Ha.	0.00	0.00	1.75	3.50	3.5	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
					25 Ha	50 Ha	50 Ha.	25 Ha					
5	Improvement of stock by dressing of existing stumps of browsable species and cut back (The DFO should inspect the area and after		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	proper marking and hammering , the dressing of live stumps can be permitted) and Gap plantation of fruit bearing trees like Aonla, Jamun, Bel, Ghular, Bargad, and Peepal by planting in 1 st year itself)												
6	Maintenance of fruit trees plantation for 5 years		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Fire protection by cleaning and maintaining the fire lines (Natural and artificial) and purchase of fire fighting equipments.	L.S.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.50
8	Empowerment of JFMCs, public awareness, training etc. and miscellaneous works/ activities that may be developed subsequently to reduce human - animal conflicts.	L.S.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	Biodiversity conservation, empowerment of BMC, public awareness training etc. and miscellaneous works/ activities that may be developed subsequently to reduce human - animal conflicts.	L.S.	2.0	1.0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
10	Monitoring and evaluation of works	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50
	Total		19.00	26.50	22.75	8.00	4.50	2.75	1.00	1.00	1.00	1.00	87.50
	+15% Escalation		2.85	3.975	3.4125	1.20	0.675	0.4125	0.15	0.15	0.15	0.15	13.125
	Grand Total		21.85	30.475	26.1625	9.20	5.175	3.1625	1.15	1.15	1.15	1.15	100.625

Abstract (Rs. in Lakh)

Dhamtari	711.85
Kanker	178.825
Keshkal	218.50
USTR	100.625
Total	1209.80


 Principal Chief Conservator of Forests (WL) cum
 CWLW, Chhattisgarh



PD/DMT/RV/Forest/6407

Date: 11.09.2023

To,

The Divisional Forest Officer
Forest Division-Dhamtari
Dist-Dhamtari (C.G.)

Sub: Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661) - Compliance of condition stipulated in Forest clearance - Reg.

Ref: (i) IRO, MOEF&CC, Raipur letter No.FC-III/IROCH-04/2022/673 dt.12/04/2022
(ii) IRO, MOEF&CC, Raipur letter No. FC-III/IROCH-04/2022/727 dt.24.05.2022
(iii)IRO, MOEF&CC, Raipur letter No.FC-III/IROCH-04/2022/991 dt.27.10.2022.
(iv) IRO, MOEF&CC, Raipur letter No. FC-III/IROCH-04/2022/1083 dt.02.12.2022
(v) IRO, MOEF&CC, Raipur letter No. FC-III/IROCH-04/2022/1450 dt. 04.07.2023

Sir,

Please find enclosed herewith compliance of condition & additional condition stipulated in IRO, MOEF&CC letters referred at Sr.No.01 to 05 in appendix-1.

2. It is requested to take necessary action for grant of Stage-2 approval.

Encl: As above


Project Director

Copy to:-

1. APCCF (Land Management), Aranya Bhawan, Naya Raipur - for kind information please.

Copy also to:-

1. CGM (Tech) cum Regional Officer-Chhattisgarh, NHAI, Raipur-for kind information, please.
2. GM (Tech.), Chhattisgarh, NHAI-HQ New Delhi - for kind information please.

Appendix-I

Stage-1 compliance of conditions stipulated in Forest Clearance (FC) which has been accorded by MoEFCC Regional office, Chhattisgarh vide letter no: - FC-III/ROCH-04/2022/673 dated 12/04/2022.

AND

Additional condition stipulated conditions in IRO, Raipur letter no FC-III/ROCH-04/2022/727 dated 24-05-2022.

AND

Additional condition stipulated conditions in IRO-Raipur letter no. FC-III/ROCH-04/2022/991 dated 27-10-2022.

AND

Additional condition stipulated conditions in IRO-Raipur letter no. FC-III/ROCH-04/2022/1083 dated 02-12-2022

AND

Additional Conditions stipulated in IRO letter no. FC-III/ROCH-04/2022/1450 dated 04/07/2023.

Name of the Project: - "Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661)

Online Proposal No: - FP/CG/ROAD/118868/2021

Stage-1 Stipulated conditions issued vide letter no. FC-III/ROCH-04/2022/673 dated 12/04/2022.		
SL.	Stipulated condition	Compliance by NHA-PIU Dhamtari
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed. Legal status of the Forest Land will not be changed and will remain be the same as it is.
Compensatory afforestation		
(ii)	a. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 457 ha spread in 19 patches in 03 forest ranges in Mahasamund Forest Division. Orange Forest Area in Rajnandgaon division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted, and monoculture of any species may be avoided.	Agreed and complied. The cost of Compensatory afforestation is already deposited in CAMPA account, and it is also updated on https://parivesh.nic.in/ , details of the same is attached as Attachment-1(Receipt of payment (NEFT-reference No.P146220171195301 dt.26.05.2022) Selection of plant species is under preview of the concerned Forest Department (office of DFO-Mahasamund) and during CA plantation it will be taken care based on site specific suitability.
(iii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on	Agreed and complied Amount as per DFO Dhamtari demand vide letter no.चि./जी/2526 dt.09.05.2022 has been deposited in CAMPA fund Chhattisgarh vide NEFT No.P146220171195301 dt. 26.05.2022. The CA cost include maintenance of plants for a

	the CA land shall be deposited in advance with the current wage rate to the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	period of 10 Years. User agency NHAI-PIU Dhamtari is fully agreeing to adhere the condition in case revise/increase as per supreme court of India direction/ Government decision.
	NPV:	
(iv)	a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at present rate for the 228 0425 ha (180.1675 ha at present and 47.875 ha after ESZ notification) forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2005 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 6-1/1998-FC (PL.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2008-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	Agreed and complied. As per office of Dhamtari Demand note issued vide letter no- मा.चि./जी/2526 dt.09.05.2022, amount against CA , NPV and Wildlife Management Plan , Rs 818152379/- (Eighty one crore eighty one lakh fifty two thousand three hundred seventy nine) has already been deposited in CAMPA fund under NEFT reference no- P146220171195301 dt.26.05.2022. May please refer Attachment-1 for payment receipt.
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed and will be complied. In case additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, User Agency NHAI-PIU Dhamtari is agreed to pay. Undertaking for the same is already given in forest land diversion proposal and as compliance of this stage-1 stipulated condition, undertaking is given.
(v)	Forest clearance is agreed only for diversion of 180.1675 ha forest areas under FC Act, and it does not include forest areas falling under ESZ/ PA.	Agreed and complied. In 7th REC meeting dated 24/05/2022 again this forest proposal placed in which it is decided and communicated to User Agency vide letter no:- F. No. FC-III/ROCH-04/2022 - 727 dated 24/05/2022 under serial no 1 (v) which read " The Committee further opined that as the proposed alignment passes through the notified tiger corridor by the NTCA, the proposal need the Wildlife Clearance and accordingly suggested that User Agency shall take the permission from NBWL". Further, Wildlife Clearance is accorded vide letter/File no.6-112/2022 WL dated 3/07/2023. Accordingly, compliance of this stipulated condition is no more required. Attachment-2 Wildlife clearance letter.

G

44

(vi)	For the stretch from 89.641 to km 124.661 (35.020 km) falling under default (10 km) ESZ of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve and constituting an area of 47.875 ha, the User Agency shall obtain the revised ESZ notification or approval from the NBWL as mandated under the FC Act, rules and guidelines. In case any realignment or other changes are suggested by NBWL or MoEF & CC during the course, the consequential changes, if any, will be effective in the "In Principle" FC approval accordingly.	<p>Complied,</p> <p>Wildlife Clearance is accorded in 72nd meeting of standing committee of National Board for Wildlife dated 11th May 2023 (WL-06/20/2023-WL).</p> <p>There is no change in alignment is suggested by standing committee of National Board for Wildlife.</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter.</p>
(vii)	Wildlife Conservation and Management Plan approved by Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh as per the WII guidelines shall be submitted before Stage-II approval.	<p>Complied.</p> <p>Wildlife Management Plan is part of Wildlife Clearance Proposal and already submitted through appropriate channel. After approval of Wildlife Management Plan from office of Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh it is submitted to Wildlife division of MoEFCC, New Delhi.</p> <p>Wildlife clearance proposal is already accorded vide letter dated 03.07.2023.</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter.</p>
(viii)	The state shall ascertain whether proposed wildlife area or any portion thereof falls in the declared Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor. In case of any area falling in the Tiger Corridor, the User agency shall take necessary approval from NTCA, the same shall be submitted before Stage-II approval:	<p>Agreed and complied.</p> <p>Proposed project road alignment traverse through default ESZ (@10 km from PA boundary) between km 89.641 to km 124.661 (35.020 km). Also, Project road alignment cross Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor between km 105+000 to Km 108+500.</p> <p>Wildlife Clearance is accorded in 72nd meeting of standing committee of National Board for Wildlife dated 11th May 2023 (WL-06/20/2023-WL). Since, project road alignment also traverses through tiger corridor Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda, Wildlife division of MoEFCC through its official channel has consulted with NTCA and only after the recommendation of NTCA Wildlife Clearance is accorded.</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter & NTCA recommendation.</p>
(ix)	Total 354 nos, of structures proposed in 81.817 km road length (Road length in Forests 47.875 Km), proposed cross structures for movement of animals are at the interval of 200-250 meters. The suitability of the structures and their quantity will be examined by the Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh and the prescribed statutory authorities in the management plan submitted the User Agency, as per the extant guidelines, the same shall be submitted before Stage-II approval.	<p>Agreed and being complied,</p> <p>It is to undertake that a 354 nos. of cross structures are provided in a road length measuring 81.817 km at identified locations for the crossing of surface water, wild animal, farmers etc.</p> <p>Dedicated structures for wildlife movement are 26 number of cross structures, 1 tunnel having length 2.79 km 3 nos. of viaduct having total length 960 meter.</p> <p>Location to provide cross structures for smooth passage of wild animal are already identified strictly under consultation of Forest department.</p> <p>Further, WII official Dr. Bivash Pandav, Scientist G of WII</p>

G

4

		<p>visited the project site on 12th and 13th June 2023 and comments and recommendation shows that "The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km.</p> <p>Also, in 72nd meeting of standing committee of National Board for Wildlife dated 11th May 2023, it is suggested under condition no.5 "All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/cc culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians, and small animals. Further, it is to undertake that all the prescribed guidelines, recommendation of NBWL in its Wildlife clearance letter through stipulated conditions will be strictly followed during execution of project.</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter.</p>
(x)	The clearance from Project Elephant Division, if required, shall be before the Stage-II approval:	<p>Complied</p> <p>Clearance from Project Elephant Division is obtained.</p> <p>Attachment-3 Clearance letter from Project Elephant Division.</p>
(xi)	Out of the total project affected 87,613 trees only 68,013 will be felled in 30 meters of Row and 19600 trees falling in the on either side of the road will be kept intact. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Tree felling will be accomplished under closed supervision of the concerned Forest officials. Undertaking for barest minimum tree felling is already given in Forest Land Diversion Proposal.</p> <p>Further, IRO Chhattisgarh on dated 2/12/2022 vide letter no. FC-III /IROCH-04/2022/083 (of 12th REC meeting dated 29.11.2022) allowed felling of standing tree within RoW of 45 meter under condition no. (a) which reads "The Committee approved the proposal for felling of trees in 45m RoW of the project, the User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department"</p> <p>All the cost incurred against felling of standing tree will be deposited as per demand note of the concerned forest department.</p>
(xii)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable, before the Stage-II approval.	<p>Agreed and complied.</p> <p>Environmental Clearance has already been awarded on 12/05/2022 vide EC Identification No. - EC22A034CG113144, File No. - 10-3/2020-IA.III.</p> <p>May please refer Attachment-4, Copy of Environmental Clearance letter.</p>
(xiii)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal	<p>Agreed and complied.</p> <p>Fund as per DFO Dhamtari demand vide letter no. वि/जी/2526 दि.09.05.2022 against NPV, CA and</p>

	(https://parivesh.nic.in);	<p>implementation of Wildlife Management Plan has been deposited in CAMPA fund of Chhattisgarh through e-portal vide NEFT No.P146220171195301 dt.26.05.2022. The amount against demand note is already deposited and the same is reflected on parivesh portal.</p> <p>Please refer Attachment- 1 for receipt/screenshot.</p>
(xiv)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector,	<p>Agreed and complied.</p> <p>All the required proceedings of FRA 2006 are completed and FRA certificate from the concerned District Magistrates are issued</p> <p>May Please refer Attachment-5, FRA certificates.</p> <p>May please refer Annexure-14 for undertaking and submission receipt.</p>
(xv)	Strip plantations on both sides and central verge of the road as per the IRC norms shall be raised by the State Forest department by planting tall seedlings of 8-10 feet in height at the cost of User Agency, further, same shall be protected by chain linked fencing at least for initial three years of its growth. In forest patches, plantations of ornamental species should be avoided, and preference shall be given to native forest tree species including fruit bearing tree species, like mango, banyan, tamarind, etc;	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Provision has been made for Avenue and median plantation in Concession Agreement.</p> <p>IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation) and Guideline under Green Highway policy will be followed in true respect.</p> <p>During plantation suggestion for selection of species will be obtained from the concerned forest department. All the cost of Avenue plantation will be borne by the User Agency.</p> <p>Since, in forest area width is already restricted to save standing Forest Tree, scope of avenue plantation will be limited to those patches where forest trees are not available.</p>
(xvi)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Forest Areas;	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Speed regulation signage will be installed at appropriate location as per IRC guideline (IRC: SP: 55:2015& IRC:SP:67-2012) and also as per suggestions of concerned forest department to aware the drivers and other road users specially keeping in view of presence of wild animal in/along the forest area.</p>
(xvii)	<p>User Agency in consultation with forest department shall prepare 26 Underpasses, one tunnel of length 2.83 km and 3 viaducts having total length 960 meter along with the following structures.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 29 nos. of Monkey Canopy ➤ 5 nos. of Major Bridges, 37 nos. of Minor Bridges, ➤ 3 nos. Viaduct, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP, 33 nos. of LVUP and 233 nos. of Box culverts. 	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Provision of 26 nos. of dedicated underpasses for wild animal, one tunnel having length 2.79 km and 3 viaducts having total length 960 meter along with 29 nos. of Monkey Canopy, 5 nos. of Major Bridges, 37 nos. of Minor Bridges, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP, 33 nos. of LVUP and 233 nos. of Box culverts are already provisioned in project.</p> <p>Design of these structures are already finalized and will be constructed while executing the project.</p> <p>Further as per stipulated condition no. 1 of Wildlife Clearance which reads "The Animal Passage Plan needs to be examined by WII", WII official Dr. Bivash Pandav, Scientist G of WII visited the project site on 12th and 13th June 2023 and comments and recommendation shows that "The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively</p>

		<p>covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km. The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision with wild animals.</p> <p>The project proponent agrees to adhere the all recommendations of Forest Department, Wildlife Department as well as recommendation of WII.</p> <p>May please refer Attachment-6, WII recommendation letter.</p>
(xviii)	<p>The User Agency in consultation with Forest Department shall provide under/over pass for safe passage of wild animals at suitable places as per Wildlife Institute of India's manual entitled "Eco friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" published in 2016;</p>	<p>Agreed and complied.</p> <p>During study for preparation of Wildlife Management detailed consultation and site visit along with concerned Forest and Wildlife officials are done and accordingly passage plan for smooth passage of wild animals is prepared which is also approved by CWLW and it became part of Wildlife Proposal. Wildlife Clearance is already granted vide letter dated 03.07.2023. The Wildlife Management Plan is in the line of guidelines given in Eco friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" published in 2016, prepared by WII, Dehradun.</p>
(xix)	<p>NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost.</p> <p>A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.</p>	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>NHAI through Concessionaire or other separate agency, a separate nursery for 50,000 seedlings will be established once project road alignment is established and significant construction work commenced.</p> <p>Based on recommendation/suggestion of the concerned Forest Department, preference will be given to plant local species of bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local trees.</p> <p>Forest land diversion is applied for project road located between km 42+844 to Km 124.661, measuring total length 81.817 km. Out of these 81.817 km, project road length under Forest patch/area is 47.88 km where PRow is limited and avenue plantation is not provisioned.</p> <p>Further, in remaining road length i.e 33.937 km which can accommodate (as per IRC:SP:21:2009) approx. 500 trees in 2 row plantation either side at plant to plant interval 8 meter. In such a way in 32 km road (excluding opening width of cross drainage approx. 2 km) a total 500 tree x 32 km= 16,000 trees can be planted.</p> <p>Further, to comply with the stipulated condition of Stage-1, pertain to plantation of 50 % of 50000 tree (i.e 25000) in vicinity of project road, it is to undertake that 16000 trees will be planted within PRow of project road and for remaining (25000-16000=9,000 tree) 9000 tree, User Agency will explore the possibility to plant these tree along the project road in available space of Forest land and Government/panchayat land with prior permission/ NOC from the concerned department/Panchayat.</p> <p>Attachment - 6 for WII recommendation report.</p>
(xx)	The layout plan of the proposal shall not	Agreed and will be complied.

	be changed without prior approval of Central Government.	Layout plan of proposed project will not be changed without permission of Central Government.
(xxi)	No labour camp shall be established on the forest land;	Agreed and will be complied. No unauthorized labour camp /construction yard will be established on diverted Forest land or in nearby forest area.
(xxii)	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	Agreed and will be complied. For the purpose of cooking, User Agency through construction contractor, commercial LPG will be provided to all construction workers engaged in project.
(xxiii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Agreed and will be complied. Boundary of diverted forest toward project road will be demarcated as per direction and under supervision of forest department. Cost of the same will be borne by user agency (NHAI-PIU Dhamtari, Chhattisgarh).
(xxiv)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	Agreed and will be complied. It is ensured that no new road/haul road/path will be constructed for travelling or transportation of construction material for project road other than forest land diverted and for which forest clearance accorded.
(xxv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	Agreed and noted.
(xxvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	Agreed and will be complied. It is ensured that forest land which is diverted for this project will not be used for any purpose other than the construction of this project road.
(xxvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	Noted and agreed. It is ensured that diverted forest land for proposed project will not be transferred to any other agencies, department or individual under any circumstances without prior permission of the Central Government.
(xxviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	Agreed and noted. As of now no violation of Forest conservation Act, 1980 has been committed on this project. User Agency, NHAI-PIU Dhamtari, Chhattisgarh will adhere all the conditions stipulated in stage-1 Forest Clearance of this project. In case any violation reported, User Agency will be fully responsible for it and appropriate action might be initiated.
(xxix)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the	Agreed and will be complied. All the conditions/directions issued by MoEF&CC from time to

G

G'

	interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:	time in the interest of conservation and development of forest & wildlife will be complied.
Additional condition stipulated in MoEFCC, 7th REC-Chhattisgarh meeting dated 24-05-2022 and issued vide letter no- FC-III/ROCH-04/2022/727		
1	The Committee considered the above-mentioned proposal and various facts related to the proposal in the factsheet prepared by the Integrated Regional Office, Raipur and in the proposed file submitted by the Government of Chhattisgarh. The APCCF, Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh and the representatives of the user Agency were also present in the meeting. After examination of the proposed and interaction with representatives of the user Agency, the Committee noted as under:	Noted and User agency fully agreed with the committee proceedings.
(i)	Committee noted that proposal envisages Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661), under Forest Conservation Act 1980, in favour of NHAI PIU Dhamtari District in the State of Chhattisgarh. The total forest area proposed for diversion is 228.0425 ha.	Noted and User agency fully agreed with the committee proceedings and understood that Forest Clearance has been accorded for 228.0425 hectare of forest land. Also, as per demand note of the concerned Forest Division Dhamtari issued vide letter no. चि./जी/2526 dt.09.05.2022, demand amount Rs 818152379/- is deposited in CAMPA. May please refer Attachment-1 Receipt of payment
(ii)	The Committee noted that the instant proposal was placed before the REC in its meeting dated 5.04.2022, wherein, the Committee approved the proposal subject to general, standard, and additional conditions. Accordingly, IRO, Raipur has accorded approval vide letter dated 12.04.2022.	Noted and stipulated conditions will be complied. User agency understood that any conditions stipulated in stage-I approval vide letter no: - FC-III/ROCH-04/2022/673 dated 12/04/2022 contradict with conditions stipulated in 7th REC-Chhattisgarh meeting dated 24-05-2022 and issued vide letter no- F.No. FC-III/ROCH-04/2022 with will be superseded by the stipulated condition issued vide letter no- F.No. FC-III/ROCH-04/2022 dated 24-05-2022.
(iii)	The Committee was further apprised that observed that it has been observed later on that the Site Inspection Report after the inspection of proposed area by the IRO has not been submitted. However, as the proposed area under the instant case is more than 100 ha, submission of the Site Inspection Report after inspecting the proposed area by the IRO is mandatory as per Rule 7(h) of Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016.	Noted and User agency fully agreed with the committee proceedings.
(iv)	The Committee was further noted that it	Noted and User agency fully agreed with the committee

G

B

	was a procedural mistake as the site inspection is mandatory under the Rules. The Committee was apprised that the Site Inspection has been conducted by the IRO and report has been submitted. The DIG (C), IRO, Raipur apprised the Committee that all facts as mentioned in the Form-A of proposal were inspected and no specific observation were found during inspection. It was further submitted that the CA sites identified for raising CA were also found suitable for raising plantation.	proceedings.
(v)	The Committee further opined that as the proposed alignment passes through the notified tiger corridor by the NTCA, the proposal needs the Wildlife Clearance and accordingly suggested that User Agency shall take the permission from NBWL.	<p>Agreed and being complied. Project road alignment cross Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor between km 105+000 to Km 108+500. Wildlife Clearance is accorded in 72nd meeting of standing committee of National Board for Wildlife dated 11th May 2023 (WL-06/20/2023-WL)</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter.</p>
(vi)	It was also informed to the Committee that instant exercise was only done by the IRO, Raipur to correct its earlier committed procedural mistake and no other documentary/technical parameters of proposal were re-examined/reconsidered.	<p>Agreed and noted.</p>
2	After detailed discussion, the Committee appreciated the early notice of procedural mistake by the IRO, Raipur as ensuring strict compliance of all the relevant Acts and Rules is utmost important for any Government Agency. The Committee further opined that the IRO should ensure complete scrutiny of proposals prior to its submission before the Committee. The Committee accordingly decided that the Stage-I approval to instant proposal shall be regularized, and the User Agency shall also obtain the clearance from the NBWL.	<p>Agreed and Noted</p> <p>Further, to state that Wildlife Clearance is accorded in 72th meeting of standing committee of National Board for Wildlife dated 11th May 2023 (WL-06/20/2023-WL)</p> <p>Attachment-2 Wildlife clearance letter.</p>
Compliance of additional condition stipulated conditions in IRO-Raipur letter no.FC-III/1IROCH-04/2022/991 dated 27-10-2022.		
A	Joint site inspection of the proposed project area shall be done by the IRO, Raipur with one or more REC members, representative of the State Forest Department and NHAI officials to ascertain trees to be felled in the ROW of 45m and to minimize the trees to be sacrificed.	<p>Agreed and noted.</p> <p>In pursuance of decision of REC meeting dated 20.10.2022 and direction of Inspector General of Forests, IRO, Raipur through letter No.FC-Misc/01/1IRO-RPR/2021/1005 dated:02/11/2022, DIG Forest inspected the proposed area of diversion of 228.0425 ha falling in Forest Divisions of Dhamtari, Kanker and Keshkal along with Shri. Suresh Chopane REC member, representatives of User agency (NHAI) and representatives of Chattisgarh State Forest Department on 05.11.2022 and 06.11.2022.</p>

Gr

li

		Further the inspection report is presented in 12th REC meeting dated 29.11.2022 and decision was taken to allow the felling of standing tree located within 45-meter RoW.
B	Trees of small girth among the enumerated 87613 trees shall be tried for tree translocation/ transplantation, especially the ones like <i>Terminalia tomentosa</i> , <i>Pterocarpa margi</i> , <i>Tectonagrandis</i> and <i>Shorea robusta</i> , which have very slow growth.	<p>Agreed and noted.</p> <p>Project Proponent is agreeing for translocation/transplantation of small trees mainly <i>Terminalia tomentosa</i>, <i>Pterocarpa margi</i>, <i>Tectonagrandis</i> and <i>Shorea robusta</i>, subjected to feasibility and viability ascertained by the concerned Forest Department.</p>
C	Standard Operating Procedure (SoP) suggested by MoEF&CC vide its No-7-12/2022-ROHO (Pt) dated 11/10/2022 will be followed by the U/A.	<p>Noted and agreed.</p> <p>User agency will follow all the stipulated conditions and guidelines of Standard Operating Procedure (SoP) suggested by MoEF&CC vide its No-7-12/2022-ROHO (Pt) dated 11/10/2022.</p>
D	10 times the trees felled beyond 30m-Row will be planted by the User agencies as avenue plantation or otherwise.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>User agency fully agreed to plant 10 times of the trees felled beyond 30m that is 7.5 meter either side of project road alignment. All the cost against plantation of these tree will be borne by the Project Proponent.</p>
Compliance of additional condition stipulated conditions in IRO-Rajpur letter no.FC-III/ROCH-04/2022/1083 dated 02-12-2022		
A	The Committee approved the proposal for felling of trees in 45m RoW of the project, the User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Tree felling will be accomplished under closed supervision of the concerned Forest officials.</p> <p>Considering the road geometry requirement pertain to road user safety, effort will be made by the User Agency for minimum tree felling within 45 meter PRow. All the tree felling will be done under close supervision of the concerned Forest official.</p>
B	In lieu of the translocation, block plantation of 10 times of trees felled in RoW beyond 30m will be carried out in the nearby area/Divisions identified by Forest Department. The block plantation will consist particularly of the slow-growing trees <i>Shorea robusta</i> , <i>Pterocarpus marsupium</i> and <i>Terminalia tomentosa</i> . The plantations will be facilitated by drip-irrigation and intensive care to ensure their survival. Henceforth, the plantations will be raised by the Forest Department instead of the NHAI to ensure better success. All costs including maintenance will be borne by the User	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Translocation and transplantation of eligible trees particularly slow-growing trees <i>Shorea robusta</i>, <i>Pterocarpus marsupium</i> and <i>Terminalia tomentosa</i> will be done under the close supervision and direction of the concerned forest officials. The land for block plantation in close vicinity will be selected and provided by the concerned forest department. User Agency agreeing to facilitate and bear the cost of transplantation/translocation of tree located beyond 30-meter PRow and within 45 meter as condition stipulated.</p>

	Agency and in every six month a report will be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Raipur.	
C	Avenue plantations of 10 times of trees felled in 30 m RoW will be raised by the User agencies at their own cost.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>The available road length of avenue plantation (other than forest area) is 33.937 km which can accommodate (as per IRC:SP:21:2009) approx. 500 trees in 2 row plantation either side at plant to plant interval 8 meter. In such a way in 32 km road (excluding opening width of cross drainage approx. 2 km) a total 500 tree x 32 km = 16,000 trees can be planted.</p> <p>Since, the joint enumeration of tree is completed for 45-meter proposed RoW in Forest Area, the exact number of tree felled within 30 Meter RoW will be established after all the tree are felled under supervision of the concerned Forest Department.</p> <p>If the number of felled trees is more than 16000.0 (Sixteen thousand) then to comply this condition, User Agency will plant the remaining tree in land provided by the Forest Department.</p>
Stage-I Stipulated conditions-issued vide letter no FC-III /IROCH-04/2022/1450 dated 04/07/2023		
1	The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision. It shall also comply with all the mitigation measures suggested by WII.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>This is to undertake that once the civil work is completed, fencing will be done under supervision of forest/wildlife department along the project road stretches, passing through Forest Area.</p>
2	The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>This is to undertake that all the construction work will be limited between dawn and dusk only along/near the forest area to avoid any inconvenience to wild animal.</p>
3	Any other condition imposed from time to time by forest department.	<p>Noted and will be complied.</p> <p>This is to undertake that all the condition-imposed time to time by the concerned forest and wildlife department will fully adhere by Project Proponent.</p>
4	There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Being a highway project, all the safety features including caution board, information board will be installed at appropriate location as per IRC guideline (IRC: SP: 55:2015 & IRC: SP: 67:2012) and as per suggestions of concerned forest department to aware the drivers and other road users specially keeping in view of presence of wild animal in/along the forest area.</p>
5	All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/CC culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians, and small animals.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>Keeping in view of wild animal protection, 26 nos. of dedicated underpasses for wild animal, one tunnel having length 2.79km and 3 viaducts having total length 960 meter along with 29 nos. of Monkey Canopy, 5 nos. of Major Bridges, 37 nos. of Minor Bridges, 3 nos. Viaduct, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP, 33 nos. of LVUP and 233 nos. of Box culverts are already provisioned in project. Design of these structures are already</p>

Gr

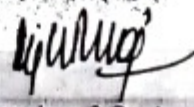
Gr

		<p>finalized and will be constructed while executing the project. Further as per stipulated condition no. 1 of Wildlife Clearance which reads "The Animal Passage Plan needs to be examined by WII". WII official Dr. Bivash Pandav, Scientist G of WII visited the project site on 12th and 13th June 2023 and comments and recommendation shows that "The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km. The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision with wild animals.</p> <p>As compliance of this stipulated condition, Project Proponent is agree to provide pipe/box culvert at every 100 meter as per site suitability in road stretches located in ESZ/ wildlife corridor for the smooth movement of small animals (reptiles, amphibians, and other small animals) Also, please refer Attachment-6, WII recommendation report</p>
6	Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.	<p>Agreed and will be complied. Provision is already made in Wildlife conservation plan for providing integrated light and sound barrier above the all underpasses located in Forest/Wildlife Area. Camouflage/cryptic coloration and site-specific landscaping will be provided at all dedicated underpass for wild animal under close supervision of the concerned Forest/Wildlife official.</p>
7	There will not be a right of passage to the public via the underpass.	<p>Agreed and will be complied. It will be insured that no approach road/ access road connects the dedicated underpass so these underpasses should only be used for wild animal.</p>
8	The Chief Wildlife Warden should have an adequate monitoring mechanism in place.	<p>Noted The compliance of this stipulated condition is to be made by the office of Chief Wildlife Warden.</p>
9	An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to Government of India.	<p>Agreed and will be complied. From the date of award of stage-II, annual compliance on stipulated condition of Forest clearance will be submitted to the State Chief Wildlife Warden.</p>

Date: - 11/09/2023

Place: - Dhamtari

Project Director
NHAI-PIU, Dhamtari, Chhattisgarh
Name: - Pankaj Ojha


Signature & Seal

PARIVESH
परिवेशMinistry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ~ My Proposals Environment Clearance ~ Only CRZ Clearance ~ My Proposals Forest Clearance ~ My Proposals Wildlife Clearance ~ Help

9:30:59 PM



Sno.	Proposal Detail	Application No.	Preregistration No. (New)	Date of the PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PP/CG/ROAD/119866/2021 Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lut-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to Km 124.661)	ROAD1198662021812611	11986681	12 Apr 2022	Ca: 401605659/- PCh: 0/- Safety Zone: 0/- SPV: 295566720/- Other: 0/- Charges1: 0/- Other: 0/- Charges2: 0/- Other: 0/- Charges3: 0/- Total: 818152379/-	Paid	Fund Demand Verified by Modal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	Demand Letter Generated Challan



F.No.6-112/2021 WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
 Indira Paryavaran Bhawan,
 Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

Date: 3rd July, 2023

To
The Principal Secretary,
 Forest Department, Aranya Bhawan,
 Medical Collage Road,
 Fafadih, Raipur 492001.

Sub: Proposal for use of 198.3084 of forest land from Udanti-Sitanadi Tiger Reserve for development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under BharatmalaPariyojana-FP/CG/ROAD/119866/2021.

Sir,
 Reference is invited to the subject mentioned above. The above proposal was discussed in the 72nd Meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life held on 25th April, 2023 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.


2. After discussion, the standing committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The animal passage plan needs to be examined by the WII.
2. The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only.
3. Any other condition imposed from time to time by forest department.
4. There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.
5. All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/cc culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals.
6. Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.
7. There will not be a right of passage to the public via the underpass.
8. The Chief Wild Life Warden should have an adequate monitoring mechanism in place.
9. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.

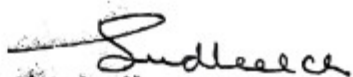
4. The Director, Wildlife Institute of India, Dehradun was requested by the Ministry for examination of the animal passage plan who based on the field inspections carried out by Wildlife Institute of India has submitted the report (enclosed) for your information and compliance.

Yours faithfully,


(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in

Copy to:

1. Chief Wild Life Warden, Forest Department, Aranya Bhawan, Medical Collage Road, Fafadih, Raipur-492001.
2. Deputy Director General of Forests, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines, Nagpur-440001 for monitoring the compliance of conditions.
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC.


(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in

Assessment of proposal on Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) Greenfield Highway in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana (Online Proposal: FP/CG/ROAD/119866/2021)

Background: Bharatmala Pariyojana is a flagship program of Government of India for the highways sector that focuses on optimizing efficiency of freight and passenger movement across the country by bridging critical infrastructure gaps through effective interventions like development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes, National Corridor Efficiency Improvement, Border and International connectivity roads, Coastal and Port connectivity roads and Green-field expressways. NHAI-PIU Dhamtari has been entrusted with the assignment of project namely Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-3) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. The proposed National Highway aims to connect Chhattisgarh with Andhra Pradesh through Odisha. The project road is green field alignments having 6 lane configuration passing through Raipur, Dhamtari, Kanker and Kondagaon districts of Chhattisgarh. Although, the project road length within Chhattisgarh state is 124.661 km which starts from Abhanpur (km 0+00) and ends at village Sabbavarun (km 124+661), the road length passing through forest and wildlife area is 44.334 km (km 42+844 to km 124+661) entailing a total diversion of 228.0425 ha of forest lands in Dhamtari (147.6694 ha), Keshkal (41.2862 ha) and Kanker (39.0869 ha) Forest Divisions of Chhattisgarh.

SBWL of Chhattisgarh state has been reconstituted. Meeting of SBWL has also been conducted on 19.12.2022. The SBWL recommended the proposal and forwarded to MWL vide letter No.F-5-29/2021/10-2 dated 20.01.2023.

Observations:

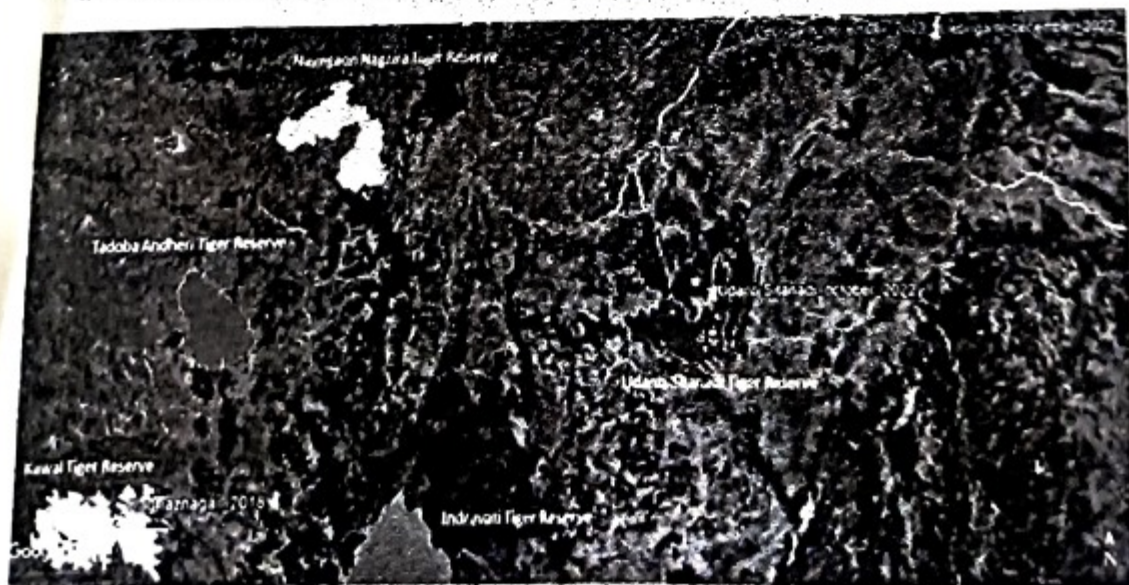
1. The proposed highway is at an approximate distance of 3.8 km from the boundary of core zone of Udanti Sitanadi Tiger Reserve (USTR; Fig. 1).
2. Approximately 35.020 km of the highway (km 89+641 to km 124+661) passes within default (10 km) Eco-sensitive zone (ESZ) of USTR (Fig. 1) entailing diversion of 64.9443 ha of forest land from Kanker and Keshkal Forest Divisions. However, the highway is 250 m away from the proposed ESZ (as per the draft notification) for USTR (Fig. 1).
3. Approximately 3.5 km of the road alignment (km 104+895 to km 108+247) is intersecting the least cost pathway (LCP) tiger dispersal corridor in between Indravati Tiger Reserve-Udanti Sitanadi Tiger Reserve-Sunabeda Wildlife Sanctuary delineated by NTCA and WII in 2014 (Fig. 1). Total forest patch length in this corridor section is 5.6 km approximately.
4. The highway passes through a landscape block consisting of Sunabeda Wildlife Sanctuary of Odisha and Udanti-Sitanadi Tiger Reserve of Chhattisgarh which is not only important for tiger recovery but also home to a small wild buffalo population in central India. As per 2018 cycle of tiger estimation, tiger population in this block is estimated to be 3 within a span of 764 km². Biotic pressure on the forest and the corridor is high as the area is affected with Left Wing Extremism. The corridor complex of Sunabeda-Udanti-Sitanadi also connects Indravati Tiger Reserve both to Udanti-Sitanadi Tiger Reserve and to Pann Wildlife Sanctuary. Due to the large size of the forested habitat in this landscape, the area has potential for future tiger recovery through protection, restoration of law and order and management to support prey.

Fig. 1: Location of the proposed highway in relation to Udanti Sitanadi Tiger Reserve (USTR), Eco-sensitive zone (ESZ) and least cost pathway tiger dispersal corridors. Default (10 km) ESZ is depicted in purple color while blue line indicates the proposed ESZ (as per the draft notification) for USTR



5. Based on National Repository of Camera Trap Photographs of Tigers analysis, there is a recent instance of dispersal of a tiger from Kagaznagar Forest Division in Telangana to Debrigarh WLS in Odisha via USTR in Chhattisgarh (Fig. 2). This demonstrates potential permeability of the corridors fostering tiger movement in the landscape.
6. As per 2018 cycle of all India tiger estimation, the landscape has presence of mammalian species such as leopard, sloth bear, dhole, wolf, hyena, jackal, elephant, gaur, nilgai, chital, sambar and barking deer. Many of these species are endangered and under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

Fig. 2: Tiger movement in the landscape. This tiger individual was first photographed in 2018 in Kagaznagar in Telangana and has since moved to Odisha via Udanti Sitanadi TR.



31 p. 000

7. The project proponent has already examined four alternatives and the current alignment has been proposed because of better technical feasibility and involvement of diversion of lower extent of forest area. In general P.Ro.W of the proposed road is 60 m while in forest area it is restricted to 45 m. Nevertheless, the R.O.W has an estimated 40,000 trees which may need to be removed for the implementation of the project.

8. A project of this scale of national importance needs to be implemented. However, this has to be executed with adequate appropriate mitigation measures for wildlife so that biodiversity and natural resources conservation is not compromised.

9. **Animal Passage Plan:-**

NHAI has already submitted an animal passage plan which proposes dedicated wildlife underpasses and overpasses at 26 locations and canopy bridges for arboreal species at 29 locations. Altogether, 5 major bridges, 37 minor bridges, 14 VUPs, 2 VOPs, 33 LVUPs and 233 box culverts have been proposed. In addition, a 2.8 km long tunnel and three viaducts have been proposed for the section of the highway passing through the corridor area. Vertical clearances for the most of the structures have been proposed as 5 to 7 m. Estimated capital cost of project is Rs 4,068.16 crores & estimated expenditure on Wildlife management plans is 1205.20 lacs which has already been deposited to Forest Department in CAMPA fund by user agency.

10. For reviewing and vetting/modification of the submitted animal passage plan by NHAI and finalize the mitigation measures after causing a site appraisal, NTCA opined for constituting a committee comprising of representatives from NTCA, Chhattisgarh Forest Department, NHAI and WII. NTCA vide office memorandum No.7-21/2022-NTCA dt.23.03.2023 has constituted a team to in connection with proposal of Raipur-Visakhapatnam (Ch.0+000 to Ch.124.661) (Online proposal No.FP/CG/ROAD/119866/2021), the details of team members are as below:-

- (i) Representative of Chief Wild Life Warden, Chhattisgarh - Member
- (ii) Representative of NHAI PIU Raipur - Member
- (iii) Dr. Kausik Banerjee, Scientist, Tiger Cell, NTCA, New Delhi - Member
- (iv) Sh Hemant Bhaskar Kandi, AIGF, NTCA, Regional Office Nagpur - Member Convener

The terms & reference of the said team are :- to cause site appraisal for reviewing the animal passage plan proposed by NHAI & suggest appropriate mitigations measures.

11. Thereafter, it was decided vide letter dated 13.04.2023 that, a visit plan has been proposed on 21st April to 22nd April, 2023 by Member of NTCA for Raipur-Visakhapatnam Green Field Economic Corridor (proposal No.FP/CG/ROAD/119866/2021) along with other committee members.

12. Accordingly a site visit has been carried out by committee members along with officials of Forest Department and NHAI on 21st April 2023 to 22nd April 2023. After site visit, GIS appraisal and review of Proposed mitigation plan, committee has given following recommendation.

Recommendations:-

Mitigation proposed by the user agency is adequate for the section of road passing through ESZ and wildlife corridor. Looking at the significance of the road, project can be recommended with additional minor condition that

- There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.
- All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals.
- Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which tiger corridor is passing.
- There will not be a right of passage to the public via the animal underpass.
- The CWLW should have an adequate monitoring mechanism in place.

Mam
22/04/23
AIGF NTCA RO NAGP

(Signature)
22/04/23
(Director Kanger
Valley MP)

Asin
22/04/23
Project Director
PSU. Dharmtar
NHAT (G.B.)

F. No. 7-2/2021-PE
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(Project Elephant Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
for Bagh Road, Aliganj,
New Delhi-110003

Dated 16th December, 2021

To

The Principal Chief Conservator of Forests (WL)
& Chief Wildlife Warden,
Department of Forests,
Government of Chhattisgarh,
Aranya Bhawan, Raipur -492001
Chhattisgarh.

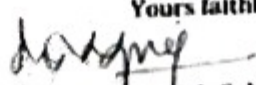
Sub: Development of economic corridors, Inter Corridors, feeder routes and Coastal road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/package -2) Raipur- Visakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661 km) (Length 124.661 km) in the state of Chhattisgarh by National Highway Authority of India under Bharatmala Pariyojana-reg.

Sir,

With reference to your letter dated 25.08.2021 regarding Development of economic corridors, Inter Corridors, feeder routes and Coastal road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/package -2) Raipur- Visakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661 km) (Length 124.661 km) in the state of Chhattisgarh by National Highway Authority of India under Bharatmala Pariyojana and submission of Wildlife Management and Conservation Plan by the User Agency as per conditions laid by the Impact Assessment Division of MoEFCC, Govt of India vide its letter 10-3/2020-IA.III, dated 02.03.2020.

In this regard it to state that the Chief Wildlife Warden may consider to approve the said Wildlife Management and Conservation Plan in light of field conditions and to meet the requirements for elephant habitats & corridors including necessary mitigation measures, as prescribed in Wildlife Institute of India guidelines for 'Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife', subject to necessary approvals under FC Act 1980 and by Standing Committee of NBWL, if required, and in consonance with Hon'ble court order (s) and NGT order(s), for the time being in force and as applicable in the matter.

Yours faithfully,


(Dr. K. Muthamizh Selvan)
Scientist 'D' (Project Elephant)
Email id. km.selvan@gov.in
Telephone No. 011-24695067

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environment Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

To,

The Project Director
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU DHAMTARI
Block F-6 Shivala Greens, Shivala Road, Dhamtari, Dhamtari, Chhattisgarh-
493773

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the Ministry vide proposal number
IA/CG/NCP/131198/2019 dated 15 Aug 2021. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

- | | |
|---|--|
| 1. EC Identification No. | EG22A034CG113144 |
| 2. File No. | 10-3/2020-IA.III |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | A |
| 5. Project/Activity including
Schedule No. | 7(f) Highways |
| 6. Name of Project | Development of Economic Corridors, Inter-
corridors and feeder routes and Coastal
road primarily to improve the efficiency of
freight movement in India under
Bharatmala Pariyojna Lot-3/Odisha &
Jharkhand/Package-2, (Ch 0.00 - Ch
124.661 km) |
| 7. Name of Company/Organization | NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF
INDIA PIU DHAMTARI |
| 8. Location of Project | Chhattisgarh |
| 9. TOR Date | 02 Mar 2020 |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 12/05/2022

(e-signed)
Amardeep Raju
Scientist E
IA - (INFRA-1 sector)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC Identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote Identification
number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

2. The above mentioned proposal was considered by the Expert Appraisal Committee (EAC) for Infrastructure, CRZ and other miscellaneous projects in its 271st meeting on 26th August, 2021.

3. The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) through National Highways Authority of India (NHAI) has decided the assignment of Development of Economic Corridors, Inter-corridors and feeder routes and Coastal road primarily to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2 having length of proposed alignment 464.662 km (which is totally green field) which starts from near Abhanpur (ch. 0.000) and ends at Sabbavaram village in Vishakhapatnam district.

4. The proposed NH is a Greenfield alignment project and proposed for 6 lane carriageway. The project highway starts at CH: 0+000 (21°05'18.85"N 81°45'01.40"E) from Jhanki village in Abhanpur Tehsil, Raipur district and ends at design Ch. 124+661 (20°01'44.59"N 81° 51'58.13"E) at Marangpuri village of Baderajpur tehsil in Kondagaon district in the state of Chhattisgarh having a total length of approx. 124.661 Kms. The proposed RoW is 60 m in general & 45 m in Forest area.

5. The proposed project falls under 7(f) - Highway, Category-A, as per EIA notification 2006. Total investment/cost of the project is Rs 366714 Lakhs (3667.14Cr).

6. Terms of Reference (ToR) of the proposal was considered in 230th Meeting on 29th January, 2020 and the ToR was granted by EAC vide letter no. F. No. 10-3/2020-IA.III, dated 02.03.2020 and Amendment ToR was granted by EAC vide letter no. F. No. 10-3/2020-IA.III, dated 04.03.2021.

7. Public Hearing was conducted in Raipur, Kanker, Kondagaon and Dhamtari districts as following:

S No	Date	Location
1	07.01.2021	Office of the Chief Executive Officer Janpad Panchayat Abhanpur, Tehsil- Abhanpur, District Raipur
2	28.01.2021	Govt. Higher Secondary School, Dudhawa, Tehsil- Narharpur, Dist- Kanker
3	05.02.2021	Govt. Higher Secondary School, Vishrampur, Play Ground Vishrampur, Dist- Kondagaon
4	15.02.2021	Kurud Stadium, Tehsil- Kurud, Dist- Dhamtari

8. Landuse/Landcover of the proposed project site is as following:

S. No.	Particulars	Area (sq. km)	Percentage (%)
1.	Agricultural Land	151.34	59.07
2.	Dense Forest	35.55	13.88
3.	Land With/Without Scrub	12.19	4.76
4.	Open Forest	36.85	14.39
5.	Plantation	0.26	0.10
6.	Settlement	13.98	5.46
7.	Water Body	6.01	2.35
	Total	256.19	100

9. The natural drainage of the project impacted area shall be maintained through improvement of 174 nos. of culverts, 06 nos. of major bridges and 34 nos. minor of bridges.

One tunnel has also been proposed at Ch. 106+820 to Ch. 109+650 having total length of 2.830 km. The proposed alignment does not pass through any flood prone area.

10. The total water requirement is 3830411 KL during construction and will be extracted from local surface water resources i.e. from local surface/ground water (which is easily available) after getting necessary permission from concerned authority by the appointed contractor. Extraction of Ground water is not proposed.

11. Land acquisition and R&R issues: The land acquisition for the proposed highway is 684.475 ha out of which 228.0425 ha is forest land and 456.4325 ha is Non-Forest Land. The stage-1 Forest Clearance is obtained vide letter No F.No. FC-III/ROCH-04/2022/673 dated 12.04.2022. The proposed RoW of the project is 60 m in General & 45 m in Forest.

Sl.No	State	Type of Land	Area in Ha.	% Area
1	Chhattisgarh	Non-Forest Land	456.4325	66.68
2		Forest Land	228.0425	33.32
	Total		684.475	100

12. Adequate compensation would be paid as per the measurement and prevailing norms of state government. Further, the compensation towards the acquisition of land will be made as per the provisions of the NH Act 1956 and applicable clauses and procedures as laid down in the RFCT LARR Act, 2013. The estimated cost for Rehabilitation & Resettlement including land cost has been worked out to Rs. 227.61 Crores.

13. The proposed alignment does not pass through any Wildlife Sanctuary/National Park and its eco sensitive zone. However the proposed alignment falls within 10 km boundary from Sitanadi Wildlife Sanctuary. The alignment is being fixed in consultation with the forest department so that after publishing the final ESZ notification the proposed alignment will be away from the ESZ boundary. Further an application for SBWL and NBWL is submitted in Parivesh portal for the clearance of Wildlife as the Notification of ESZ is in draft stage. The proposed project does not pass through any CRZ locations.

14. Waste Management: About 500 kg/day during construction phase and 100 kg/day (approx.) during operation phase at tolls and wayside amenities area within PROW may be generated. Bio degradable waste shall be disposed through bio composting and other waste through landfill site.

15. Tree cutting: The alignment will involve cutting of approx. 38,433 (At Forest land: 25,665 nos. of trees and at Non Forest land: 12,768 nos. of trees). The proposal is as per IRC SP-21 an available ROW apart from the statutory requirement/Local Law.

16. Energy conservation: Provision for solar power plant has been recommended in the nearby villages and its budget have been incorporated in EMP budget.

17. Rain Water Harvesting: Rainwater harvesting structures shall be provided at the interval of 500 m on either sides of carriageway as per availability of RoW and depending on the water table of first aquifer. The cost for construction of 180 rainwater harvesting structures is Rs 7.50 Crores including its maintenance.

18. Employment potential: During the construction of the road project around 1000 persons would be employed temporarily. However due to construction of toll plazas approx. 100 persons will be employed on permanent basis.

19. Benefits of the Project- The proposed project would act as the prime artery for the economic flow to this region. It will enhanced connectivity between rural & urban population, which will benefit the all sections of the society like general population, small-medium-large scale industries, farmers, businessmen etc. It will improve higher education & modern health facilities. It will improve economic scenario of the state and country. Faster transportation will strengthen tourist development in the area. Improved road connectivity will help in better implementation and management of government schemes.

20. Details of Court cases: No court case is pending against the proposed project.

21. To minimize the wild animal road accidents and ease of their movement from one area to another while crossing the road, it is proposed to construct viaducts and under passes at critical points considering the norms laid down by WII (2016) "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" and as identified in the wildlife conservation plan. The estimated expenditure on wildlife management plan would be 1205.20 lakh considering that the cost of Highway is 4068.16 Cr.

22. The EAC based on the information submitted and clarifications provided by the project proponent and detailed discussions held on all the issues during 271st meeting on 26th August, 2021, recommended the project for grant of environmental clearance with stipulated specific conditions along with other Standard EC Conditions.

23. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has considered the proposal based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee (Infrastructure, CRZ and other Miscellaneous projects) and hereby decided to grant Environmental Clearance for the "Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000 - Ch. 124.661 km) (Length 124.661 km) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana by M/s National Highways Authority of India" under the EIA Notification, 2006 as amended, subject to strict compliance of the following specific conditions, in addition to all standard conditions applicable for such projects.

SPECIFIC CONDITIONS

- i. The environmental clearance is subject to obtaining prior clearance from the wildlife angle, including clearance from the Standing Committee of the National Board for Wildlife, as applicable, as per the Ministry's OM dated 8th August, 2019 and clearance from National Tiger Conservation Authority (NTCA) and Project Elephant, MoEFCC. Grant of environmental clearance does not necessarily imply that Wildlife Clearance and other clearances shall be granted to the project and that their proposal for Wildlife Clearance and other clearances will be considered by the respective authorities on its merit and decision taken.

- ii. All commitments made in the Wildlife Management & Conservation Plan submitted to the Ministry shall be implemented in letter and spirit. The status of implementation of Wildlife Management & Conservation Plan shall be submitted to the Regional Office of the Ministry along with 6 monthly compliance report.
- iii. Water quality and Bioassay test of Mahanadi River shall be monitored quarterly and submitted to State Pollution Control Board and the RO of the MoEFCC concerned.
- iv. Road side tree plantation of local fruit bearing species or in nearby village in collaboration with Gram Panchayats.
- v. Wildlife movement during the construction be monitored by forest department and if found necessary additional over/underpasses be developed. Provision for the same be made in the project budget.
- vi. Quarry areas shall be barricaded during mining operations. The abandoned quarry shall be developed as water reservoirs with proper fencing around quarry area. Details for Quarry area operation and rehabilitation given the EIA report shall be followed.
- vii. In all the construction sites within 150 m of the nearest habitation, noisy construction work such as crushing, concrete mixing will be stopped during the night time between 10.00 pm to 6.00 am. No noisy construction activities will be permitted around educational institutions/health centres (silence zones) up to a distance of 100 m from the sensitive receptors. All plants and equipment used in construction shall strictly conform to the CPCB/SPCB noise standards.
- viii. Traffic Control Devices/Road Safety Devices/ Roadside Furniture including various types of cautionary, informatory, regulatory as mandatory signboards, road markers, studs, etc. shall be provided at appropriate locations all along the project stretch in accordance with the specifications laid down in Manual of Specifications and Standards for Expressways (IRC: SP:99-2013) and IRC:8, IRC:25, IRC:26, IRC:35, IRC:67, IRC:79, IRC:103 and Section 800 of MORTH Specifications.
- ix. Prepare the traffic prediction report for complete project (including all packages of this project) considering the cumulative impact of the traffic on the environment and submit to the Ministry and concerned Regional Office within 3 months.
- x. All the major, minor bridges and culverts should not affect the drainage systems. Flood plains of the rivers/ drainage systems are not to be disturbed.
- xi. Afforestation using compensatory plantation in the ratio of 1:10 shall be carried out by the state forest department. Native tree species shall be provided as per the IRC Guidelines on Landscaping and Tree Plantation (IRC:SP:21-2009). Plantation should be purely of native trees and Ficus species on both sides of the alignment.
- xii. Project alignment should be managed in such a way to save the Heritage/old trees supposed to be affected by the proposed alignment.
- xiii. The proponent shall obtain permission from the competent authorities for tree

elling along the proposed alignment.

- xiv. Apart from land compensation, the loss for crop has also to be compensated.
- xv. No Ground water shall be extracted and used. Approval/permission of concerned authority shall be obtained before drawing surface water from canal or any other sources.
- xvi. Rain water harvesting pit shall be at least 3 - 5 m above the highest ground water table.
- xvii. Proponent shall keep the finish road level sufficiently elevated from ground level with provision of railing on both sides to restrict animal crossing in order to avoid the possibility of wildlife injury/death. Major water bodies have been observed in the vicinity of the proposed road alignment & may be potential human elephant conflict points, appropriate nos of animal safe passages as per the guideline framed by the Wildlife Institute of India and in consultation with Chief Wildlife Warden.
- xviii. As per the Ministry's Office Memorandum F. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September, 2020, the project proponent shall abide by all the commitments made by them to address the concerns raised during the Public Hearing. The project proponent shall initiate the activities proposed by them, based on the commitment made in the Public Hearing, and incorporate in the Environmental Management Plan and submit to the Ministry. All other activities including pollution control, environmental protection and conservation, R&R, wildlife and forest conservation/protection measures including the NPV, Compensatory afforestation etc., either proposed by the project proponent based on the social impact assessment and R&R action plan carried out during the preparation of EIA report or prescribed by EAC, shall also become part of EMP and shall be implemented.

GENERAL CONDITIONS AND IRC GUIDELINES

- i. Cut and fill works shall be carried out strictly in accordance with the design drawings proposed at the time of appraisal of the project.
- ii. Sidewalk shall be provided along the bridges.
- iii. The drain shall be at least 1m away from the toe of the embankment of the road adopting IRC guidelines. Longitudinal drains shall be provided all along the project road to ensure proper drainage of the area. In addition, adequate number of under passes and culverts to act as cross drainage structures shall also be provided.
- iv. Blasting shall be carried out during fixed hours (preferably during mid-day) or as permitted by the concerned authority. The timing shall be made known to all the people within 1000m (200m for pre-splitting) from the blasting site in all directions.
- v. Rain water harvesting including oil and grease trap shall be provided as prescribed by CGWB guidelines. Water harvesting structures shall be located at every 500m along the road. Vertical drain type rainwater harvesting structures shall be set up to minimize surface runoff losses of rainwater.

- vi. The embankments/slopes and the slopes left after cutting shall be provided with vegetative growth to avoid soil erosion.
- vii. Construction spoils including bituminous material and other hazardous materials must not be allowed to contaminate water sources and the dump sites for such materials must be secured so that they shall not leach into the ground water. The non-usable bitumen spoils shall be disposed off in a deep trench providing clay lining at the bottom and filled with soil at the top (for at least 0.5m)
- viii. Construction camps shall be proposed 500 m away from the nearest settlements to avoid conflicts and stress over the infrastructure facilities with the local community. Location for stockyards for construction materials shall be identified at least 1000m from water sources. Garbage tanks and sanitation facilities will be provided at camps.

(i) Compliance Reporting

- (a) The project proponent shall submit online six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change and also upload the same, including results of monitored data, on their company website.
- (b) For compliance of conditions during operation phase, PP shall either itself undertake the responsibility of compliance or ensure setting up institutional mechanism for compliance of conditions under intimation on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (c) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- (d) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.
- (e) Beside fulfilling obligations under Corporate Social Responsibilities as per Company's Act, 2013, the proponent has to adhere to the followings Environment Responsibilities:
 - i. The Company shall have a well laid down Environment Policy approved by the Board of Directors.
 - ii. The Environment Policy shall prescribe for standard operating process/ procedures to bring into focus any infringements/ deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions.
 - iii. The hierarchical system or Administrative Order of the company to deal with environmental issues and for ensuring compliance with the environmental clearance conditions shall be furnished.
 - iv. To have proper checks and balances, the company shall have a well laid down system of reporting of non-compliances/ violations of environmental norms to the Board of Directors of the company and/or shareholders or stakeholders at large.

NOTE:

- (i) The above conditions shall be enforced in a time bound manner
- (ii) The Environmental Clearance to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain



approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.

- (iii) The PP is under obligation to implement commitments made in the to the issues raised during public hearing Conceptual Plan/ Environment Management Plan, which forms the part of this EC.

24. Further attention of project proponent is drawn towards the following Acts/ Regulations/ Statutes/ Guidelines issued from time to time:

- (a) All the Indian Road Congress (IRC) guidelines wherever applicable may be followed.
- (b) Provisions related to tree cutting as contained in the Forest (Conservation) Act, 1980 and related rules of the respective state.
- (c) Dust Mitigation Measures stipulated for Construction and Demolition Activities as provided in the amendment Notification CSR 94(E) dated 25.01.2018 of MoEF&CC.
- (d) Provisions for use of Fly ash as building material in the construction as per stipulated under Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016.
- (e) Provisions for management of construction and demolition activities related thereto as contained in Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

25. General Instructions:

Part A

- (a) Approval/permission of concerned authority shall be obtained before drawing surface water from canal or any other sources.
- (b) The proponent shall obtain permission from the competent authorities for tree felling along the proposed alignment.
- (c) As per MoEF&CC's circular no. J-11013/41/2006-IA.II (I) dated 22.09.2008, provision shall be made for supply of kerosene or cooking gas and pressure cooker to the labourers, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, Crèche and temporary structures for living during construction phase.
- (d) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure shall be reported to MoEF&CC and its concerned Regional Office.

Part B

- (a) The project proponent shall prominently advertise it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of MoEF&CC/SEIAA website where it is displayed.
- (b) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- (c) The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors (in case of Company) or competent authority, duly prescribing standard operating procedures to have proper checks and

balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions.

- (d) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the project proponent (during construction phase) and authorized entity mandated with compliance of conditions (during operational phase) shall be prepared. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Six monthly progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- (e) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- (f) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- (g) Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

This issues with the approval of the Competent Authority.



(Amardeep Raju)
Scientist-E

Copy to:

1. Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Forest Department, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur (CG).
2. The Chairman, Central Pollution Control Board, Pariyesh Bhawan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi - 32.
3. Addl. Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of Env., Forest and Climate Change Regional Office(WCZ), Ground Floor East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines, Nagpur-440 001.
4. The Member Secretary, Paryavas Bhavan, North Block Sector-19, Atal Nagar Dist-Raipur(C.G.) 492 002,
5. Monitoring Cell, MoEF&CC, Indira Paryayaran Bhavan, New Delhi.
6. Guard File/Record File
7. Notice Board.



(Amardeep Raju)
Scientist-E

Signature Not Verified
Digitally signed by Amardeep Raju
Scientist E
Date: 5/12/2022 11:13:36 AM

(आदिवासी विकास) जिला-धमतरी (छ०ग०)

e-mail: tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone no. 07722-232142, Fax no. 07722-232143

मांक / 3070/आदि०वि०/वन अधि०/न०क०- /2022-23, धमतरी, दिनांक 21/07/2022

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
ब्लाक एफ-5 शिवराज पीन्स सिहावा रोड धमतरी
जिला धमतरी ।

विषय :- development of economic corridors inter-corridors feeder routes and coastal road of improve the efficiency of freight movement in india [lot-3/odisha&Jharkhand/package-2]Raipur-vishakhapatnam [ch 0.00-ch-92.8835 hact.] in the state of Chhattisgarh under bharatmala parlyojana . (Purpose for diversion of forest land) in Dhamtari District falls in within jurisdiction of village sargi,jhanjharkera, and kekarakhali in magariode Block. का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/3789 दिनांक 23.02.2022

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा रायपुर विशाखापटनम सिक्स लेन ऐक्सेस कन्ट्रोल हाईवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है । तद संबंध में लेख है कि उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से अनापत्ति के आधार पर अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कुरुद की बैठक दिनांक 06.05.2022 द्वारा कुल 54.7859 हे का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है । जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 14.07.2022 द्वारा अनुभाग से प्राप्त अभिमत के आधार पर 54.7859 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है ।

अतः अनुमोदन उपरांत 54.7859 हे. कलेक्टर महोदय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित है ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास धमतरी

पृ०क्रमांक / 3071/आदि०वि०/वन अधि०/न०क०- /2022-23, धमतरी, दिनांक 21/07/2022
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला-धमतरी छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
02. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल धमतरी की ओर सूचनार्थ ।
03. अधीक्षक भू-अभिलेख धमतरी को सूचनार्थ ।
04. अनुविभागीय अधिकारी राजरव एवं अध्यक्ष अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कुरुद को सूचनार्थ ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद प्रयागन मगरलोड को सूचनार्थ ।
06. संबंधित ग्राम सभा को सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास धमतरी

FORM-I

(For Linear Project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District collector, Dhamtari

Date: 18/07/2022

3025

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

1 compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 (FRA for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, It is certified that 228.0425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Project director national highways authority of india, project implementation unit dhamtari (name of the user agency) for development of economic corridors inter-corridors feeder routes and coastal road of improve the efficiency of freight movement In india [lot-3/odisha&Jharkhand/package-2]Raipur-vishakhapatnam [ch 0.00-ch-54.7859 hact.] in the state of Chhattisgarh under bharatmala pariyojana . (Purpose for diversion of forest land) in Dhamtari District falls in within jurisdiction of village sargijhanjharkera and kekarakholi in magarlode Block.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 54.7859 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01.
- The proposal for such diversion [with full detail of the project and its implications, in vernacular/local language] have been placed before each concerned gram sabha of forest - dweller who are eligible under the FRA.
- Concerned gram sabha (s) has certified that the all formalities/ processes under the FRA have been carried out that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of the sargijhanjharkera and kekarakholi in magarlode Block village is enclosed .
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram sabha present.
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it;
- The rights of primitive Tribal groups and pre-agriculture communities where applicable hav been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

Encl:as above

Collector
District-Dhamtari (Chhattisgarh)
धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर

(आदिवासी विकास) जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-mail: tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone no. 07722-232142, Fax no. 07722-232143

कमांक/307/आदि0वि0/वन अधि0/न0क0- /2022-23, धमतरी, दिनांक 21/07/2022

परियोजना निदेशक,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ब्लाक एफ-5 शिवराज ग्रीन्स सिहावा रोड धमतरी

जिला धमतरी ।

development of economic corridors inter-corridors feeder routes and coastal road of improve the efficiency of freight movement In india [lot-3/odosha&Jharkhand/package-2]Raipur-vishakhapatnam [ch 0.00-ch-92.8835 hact,] in the state of Chhattisgarh under bharatmala pariyojana . (Purpose for diversion of forest land) in Dhamtari District falls in within jurisdiction of village dokal, kotarwahi, palgaon, bedhawapathra, khairbharri, karaiha, sarangpuri, chivarri, chivarri[mal], kukarikonha, sankra [chi] in nagri Block. का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/3780 दिनांक 23.02.2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा रायपुर विशाखापटनम सिक्स लेन ऐक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है । तद् संबंध में लेख है कि उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से अनापत्ति के आधार पर अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति नगरी की बैठक दिनांक 27.05.2022 द्वारा कुल 92.8835 हे का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया गया है । जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 14.07.2022 द्वारा अनुभाग से प्राप्त अभिमत के आधार पर 92.8835 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है ।

अतः अनुमोदन उपरांत 92.8835 हे. कलेक्टर महोदय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।

सहायक आयुक्त

(आदिवासी विकास धमतरी)

पृ0कमांक/307/आदि0वि0/वन अधि0/न0क0- /2022-23, धमतरी, दिनांक 21/07/2022

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर महोदय जिला-धमतरी छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
02. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल धमतरी की ओर सूचनार्थ ।
03. अधीक्षक भू-अभिलेख धमतरी को सूचनार्थ ।
04. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अध्यक्ष अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति नगरी को सूचनार्थ ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायन नगरी को सूचनार्थ ।
06. संबंधित ग्राम सभा..... को सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त

(आदिवासी विकास धमतरी)

FORM-1

(For Linear Project)

Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Dhamtari

Date: 12/07/2022

3024

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

in compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 (FRA for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project. it is certified that 228.0425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Project director national highways authority of india . Project implementation unit dhamtari (name of the user agency) for development of economic corridors inter-corridors feeder routes and coastal road of improve the efficiency of freight movement In india [lot-3/odosh&Jharkhand/package-2]Raipur-vishakhapatnam [ch 0.00-ch-92.8835 hact.] in the state of Chhattisgarh under bharatmala pariyojana . (Purpose for diversion of forest land) in Dhamtari District falls in within jurisdiction of village dokal, kotarwahi, palgaon, bedhawapathra, khairbharri, karaiha, sarangpuri, chivarri, chivarri [mal], kukar ikonha, sankra [chi] in nagri Block.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 92.8835 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01.
- The proposal for such diversion [with full detail of the project and its implications, in vernacular/local language] have been placed before each concerned gram sabha of forest - dweller who are eligible under- the FRA.
- Concerned gram sabha [s] has certified that the all formalities/ processes under the FRA have been carried out that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of the dokal, kotarwahi, palgaon, bedhawapathra, khairbharri, karaiha, sarangpuri, chivarri, chivarri [mal], kukar ikonha, sankra [chi] in nagri Block. village is enclosed .
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram sabha present.
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it;
- The rights of primitive Trabal groups and pre-agriculture communities where applicable hav been specifically safeguarded as per section 3[1][e] of the FRA.

Encl:as above

Collector
District-Dhamtari (Chhattisgarh)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

क्रमांक/635/कले./भू.अ./ 2022
प्रति,

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

कोण्डागांव, दिनांक 22/11/2022

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.)।

विषय :-

छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्या) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/पति./प्रकाई/धमतरी/राय.-विशा./फॉरेस्ट/4143 दिनांक 17.08.2022।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला कोण्डागांव के तहसील बडेरजपुर में स्थित ग्राम गोविन्दपुर में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र RF-1154 (1.6482 हे.) एवं OA-1512 (2.5172 हे.) कुल वन भूमि 4.1654 हे. में रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण किये जाने से राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रावर्श-स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम गोविन्दपुर में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र RF-1154 (1.6482 हे.) एवं OA-1512 (2.5172 हे.) कुल वन भूमि 4.1654 हे. के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि कक्ष क्र RF-1154 (1.6482 हे.) एवं OA-1512 (2.5172 हे.) कुल वन भूमि 4.1654 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गोविन्दपुर तहसील बडेराजपुर में स्थित है, में तबानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 (प्रावर्श-ब) प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा चयनित सभापति सरपंच श्री चैतराम मरकाम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रस्तुत वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	गोविन्दपुर	झीतराम पिता सुधराम व 26 अन्य वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की सूची पृथक से संलग्न है।	2.3375

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 24.01.2022 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।


कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)

FORM-I

Annexure-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Kondagaon (C.G.)

No. 635

Dated 22.11.2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that 4.1654 hectare of forest land located at RF-1154 (1.6482 he.) and OA-1512 (2.5172 he.) proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India (name of user agency) for Construction of Raipur- Vishakhapatnam six lane excess control highway under Bharatmala Project (purpose for diversion of forest land) in Kondagaon district falls within jurisdiction of Govindpur village(s) in Badarajpur tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.1654 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to 6.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above


(DEEPAK SONI)
Collector
District Kondagaon(C.G.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क्रमांक/636/कले./भू.अ./ 2022
प्रति,

कोण्डागांव, दिनांक 22/11/2022

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.)।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्या) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/पनि./पंकाई/धमतरी/राय.-विशा./फॉरेस्ट/4143 दिनांक 17.08.2022।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला कोण्डागांव के तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम खलारी में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र RF-1151 (8.8425 हे.) एवं RF-1152 (3.7665 हे.) कुल वन भूमि 12.6090 हे. में रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण किये जाने से राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रादर्श-स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम खलारी में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र RF-1151 (8.8425 हे.) एवं RF-1152 (3.7665 हे.) कुल वन भूमि 12.6090 हे. के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि कक्ष क्र RF-1151 (8.8425 हे.) एवं RF-1152 (3.7665 हे.) कुल वन भूमि 12.6090 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम खलारी तहसील बडेराजपुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 (प्रादर्श-ब) प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा चयनित सभापति सरपंच श्रीमती सामबाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	खलारी	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरस पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 24.01.2022 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।


कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Kondagaon (C.G.)

Dated 22.11.2022

No. 636

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that 12.6090 hectare of forest land located at RF-1151 (8.8425 he.) and RF-1152 (3.7665 he.) proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India (name of user agency) for Construction of Raipur-Vishakhapatnam six lane excess control highway under Bharatmala Project (purpose for diversion of forest land) in Kondagaon district falls within jurisdiction of Khairi village(s) in Baderajpur tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 12.6090 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to F.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

(DEEPAK SONI)

Collector
The District Kondagaon(C.G.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

क्रमांक/637/कले./भू.अ./ 2022
प्रति,

कोण्डागांव, दिनांक 22/11/2022

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.)।

विषय :-

छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्या) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/पनि./पंकाई/धमतरी/राय.-विशा./फॉरेस्ट/4143 दिनांक 17.08.2022।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला कोण्डागांव के तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम मानिकपुर में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र. RF-1169 रकबा 13.7810 हे. में रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण किये जाने से राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रारंभ-स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम मानिकपुर में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र RF-1169 कुल वन भूमि 13.7810 हे. के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि कक्ष क्र RF-1169 कुल वन भूमि 13.7810 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम मानिकपुर तहसील बडेराजपुर में स्थित है, में तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 (प्रारंभ-ब) प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा चयनित सभापति सरपंच श्रीमती विजयवती की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियाव्ययन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अभ्या

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	मानिकपुर	श्री सियाराम पिता दुकालू	0.0180
02		श्रीमती सोनवारीन पिता सगरू	0.3310
03		श्री सियाराम पिता दुकालू	0.1500

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24.01.2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 24.01.2022 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।



कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Kondagaon (C.G.)

Dated 22.11.2022

No 637

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that 13.7810 hectare of forest land located at RF-1169 proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India (name of user agency) for Construction of Raipur-Vishakhapatnam six lane excess control highway under Bharatmala Project (purpose for diversion of forest land) in Kondagaon district falls within jurisdiction of Manikpur village(s) in Badarajpur tehsils.

It is further certified that :

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 13.7810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to C.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

(DEEPAK SONI)
Collector

72 District Kondagaon(C.G.)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

-:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::-

क्रमांक/638/कले./भूअ./ 2022
प्रति,

कोण्डागांव, दिनांक 22/11/2022

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.)।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्या) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/पनि./पंकाई/धमतरी/राय-विशा./फॉरेस्ट/4143 दिनांक 17.08.2022।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला कोण्डागांव के तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम सलना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र PF-P1335 (8.9129 हे.) एवं OA-1522 (1.8179 हे.) कुल वन भूमि 10.7308 हे. में रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण किये जाने से राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रादर्श-स

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम (छ.ग. उड़ीसा बार्डर तक) प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु तहसील बडेराजपुर में स्थित ग्राम सलना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि कक्ष क्र PF-P1335 (8.9129 हे.) एवं OA-1522 (1.8179 हे.) कुल वन भूमि 10.7308 हे. के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का मालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का मालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि कक्ष क्र PF-P1335 (8.9129 हे.) एवं OA-1522 (1.8179 हे.) कुल वन भूमि 10.7308 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सलना तहसील बडेराजपुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 31.01.2022 (प्रादर्श-ब) प्रदाय किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 31.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा चयनित सभापति सरपंच श्रीमती अमोलीनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अध्या

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
01	सलना	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 31.01.2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 31.01.2022 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ०ग०)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Kondagaon (C.G.)

Dated 22.11.2022

No. 638

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that 10.7308 hectare of forest land located at PF-P1335 (8.9129 ha.) and PA-1522 (1.8179 ha.) proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India (name of user agency) for Construction of Raipur-Vishakhapatnam six lane express control highway under Bharatmala Project (purpose for diversion of forest land) in Kondagaon district falls within jurisdiction of Salna village(s) in Baderajpur tehsils.

It is further certified that ;

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 10.7308 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure B to S.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

(DEEPAK SONI)

Collector
District Kondagaon (C.G.)

R-v
Forest

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांगेर

दूरभाष 07868-241550

ई-मेल landrecord1550@gmail.com

कमांक / 1424 / कले. / भू अभि. / FRA / कांगेर, दिनांक / 8 / 11 / 2022

प्रति,

जनरल मैनेजर (Tech)
(प्रोजेक्टर डायरेक्टर)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

विषय:- Preparation of DPR for Development of Raipur-vishakhapatnam Economic Corridors to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojna. Issuing of certificate under scheduled Tribe & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006-Reg.

संदर्भ:- Letter of GM (Tech) Cum Project Director National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) Letter no. PD/DMT/Rai-Vish/Forest/3549 Date 02/12/2021

—000—

विषयान्तर्गत अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे । जिसमें आपके द्वारा भारत माला परियोजना अंतर्गत ग्राम जामगांव, डब्बीपानी, शामतरा, बिहावापारा, सारवण्डी एवं ग्राम बासनवाही में भारत माला परियोजना अंतर्गत पक्की सड़क निर्माण किये जाने हेतु कलेक्टर कांगेर से अनापत्ति प्रमाण पत्र 'प्रदर्श-स' की प्रति प्रदाय किये जाने हेतु लेख किया गया है।

अतः ग्राम सभा में पारित संकल्पों के आधार पर ग्राम जामगांव, डब्बीपानी, शामतरा, बिहावापारा, सारवण्डी एवं ग्राम बासनवाही में "प्रदर्श-ब" जारी किया गया है, के अनुसार जिला स्तर से "प्रदर्श-स" प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- "प्रदर्श-स" प्रमाण पत्र।

18/11/2022
डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांगेर

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजगार्ग प्राधिकरण कांकोर के द्वारा गैरयानिकी कार्य हेतु कांकोर जिला वन मंडल कांकोर के ग्राम जामगांव में स्थित जंगल भूमि आरक्षण-211 रकबा 7.2968 हे. एवं राजस्व न भूमि ख.नं. 502/2 रकबा 0.2100 हे. ख.नं. 502/4 रकबा 0.0240 हे. ख.नं. 502/5 रकबा 0.1030 हे. ख.नं. 502/8 रकबा 0.0600 हे. ख.नं. 505 रकबा 0.0780 हे. ख.नं. 508 रकबा 0.1100 हे. ख.नं. 507 रकबा 0.1020 हे. रकबा 0.2033 हे. ख.नं. 529/1 रकबा 0.5340 हे. ख.नं. 529/14 रकबा 0.0160 हे. ख.नं. 529/3 रकबा 0.0190 हे. ख.नं. 529/4 रकबा 0.3850 हे. ख.नं. 529/5 रकबा 0.3390 हे. ख.नं. 533 रकबा 0.2750 हे. ख.नं. 551 रकबा 0.0850 हे. ख.नं. 552 रकबा 0.0610 हे. ख.नं. 553 रकबा 0.0890 हे. ख.नं. 554 रकबा 0.0580 हे. ख.नं. 555 रकबा 0.0780 हे. ख.नं. 556 रकबा 0.1010 हे. ख.नं. 557 रकबा 0.0490 हे. ख.नं. 558 रकबा 0.0390 हे. ख.नं. 559 रकबा 0.0300 हे. ख.नं. 560 रकबा 0.0300 हे. ख.नं. 561 रकबा 0.0300 हे. ख.नं. 562 रकबा 0.0480 हे. ख.नं. 563 रकबा 0.0822 हे. ख.नं. 564 रकबा 0.308 हे. ख.नं. 585 रकबा 0.0160 हे. ख.नं. 586 रकबा 0.2400 हे. ख.नं. 587 रकबा 0.0200 हे. ख.नं. 588 रकबा 0.300 हे. ख.नं. 589 रकबा 0.350 हे. ख.नं. 600 रकबा 0.1190 हे. ख.नं. 603 रकबा 0.1080 हे. ख.नं. 604 रकबा 0.1730 हे. ख.नं. 605 रकबा 0.2550 हे. ख.नं. 606 रकबा 0.1000, ख.नं. 607 रकबा 0.0880, ख.नं. 608 रकबा 0.0480 हे. ख.नं. 706 रकबा 0.2020 हे. ख.नं. 707 रकबा 0.4280 हे. ख.नं. 708 रकबा 0.4000 हे. ख.नं. 718 रकबा 0.4310 हे. ख.नं. 719/1 रकबा 0.1800 हे. ख.नं. 719/2 रकबा 0.0800 हे. ख.नं. 719/3 रकबा 0.7300 हे. ख.नं. 719/5 रकबा 0.0960 हे. ख.नं. 719/6 रकबा 0.0830 हे. ख.नं. 727 रकबा 0.2770 हे. ख.नं. 733 रकबा 0.0700 हे. ख.नं. 733 रकबा 0.0700 हे. ख.नं. 734 रकबा 0.7100 हे. ख.नं. 735 रकबा 0.1410 हे. ख.नं. 738 रकबा 0.3670 हे. ख.नं. 739 रकबा 0.0150 हे. ख.नं. 740 रकबा 0.2640 हे. ख.नं. 741 रकबा 0.0440, ख.नं. 742 रकबा 0.2000 हे. ख.नं. 743 रकबा 0.1710 हे. ख.नं. 744 रकबा 0.0100, ख.नं. 747 रकबा 0.5480 हे. कुल खसरा 63 रकबा 10.0483 हे० कुल प्रस्तावित रकबा 17.3451 हे. भूमि है जिसे नवीन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 7.2968 हे. एवं राजस्व वन भूमि 10.0483 हे. कुल भूमि 17.3451 हेक्टेयर जो ग्राम जामगांव में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा ग्राम जामगांव तहसील नरहरपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 18/09/2022 (प्रदर्श-“ब”) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत जामगांव में ग्राम सभा जामगांव के अध्यक्ष श्री कवितलाल नेताम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 18/09/2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिसको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे०में)
1.	जामगांव	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरण पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/09/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (सी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु ग्रन्थावीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 18/09/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

दिनांक 18 / 11 / 2022



नाम (डॉ. प्रियंका शुक्ला)
कलेक्टर एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांगेर

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कांकर के द्वारा गैरयानिकी कार्य हेतु कांकर जिला के वन मंडल कांकर के ग्राम डब्बीपानी में स्थित वनभूमि ओप.-472 रकबा 10.123 हे. एवं ओए. 480 रकबा 5.203 हे. कुल प्रस्तावित रकबा 15.326 हे. भूमि जिन्हे नवीन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 15.326 हे. एवं राजस्व वन भूमि निरंक है. कुल भूमि 15.326 हेक्टेयर जो ग्राम डब्बीपानी में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा ग्राम डब्बीपानी तहसील सरोना में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 18/07/2022 (प्रदर्श-"ब") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर दृष्टि है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम प्रधानत मांडरादरहा में ग्राम सभा डब्बीपानी के अध्यक्ष श्रीमती इन्दु नेताम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 18/07/2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण वें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रस्तावित वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे०में)
1.	डब्बीपानी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/07/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 18/07/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

दिनांक 18 / 11 / 2022



नाम (डॉ० प्रियंका शुक्ला)
कलेक्टर एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकर

114

18-11-2022

प्रदर्शक

प्रमाण पत्र

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण काठेर (क) द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु, काठेर (क) के वन भूखण्ड काठेर (क) ग्राम शामतारा में स्थित नवीन 470 एकड़ 3.7082 है, कुल प्रस्तावित रकबा 3.7082 है, भूमि है जिसे नवीन रास्ते के निर्माण हेतु प्रयोजन किया जाता है, क वन भूमि प्रत्यक्ष रूप से वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता, अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन)।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत समूहों प्रक्रिया को पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा समूह प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 3.7082 है, एवं राजस्व वन भूमि निरंक है, कुल भूमि 3.7082 हेक्टेयर जो ग्राम शामतारा में नवीन रास्ते के निर्माण हेतु प्रयोजन की जाती है, तथा ग्राम शामतारा सहस्रीय सरोना में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं इससे पारित प्रस्ताव दिनांक 17/09/2022 (प्रदर्शक-“ब”) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर प्रमाणित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम प्रभावित शामतारा में ग्राम सभा शामतारा के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार नेताम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/09/2022 में रखा गया था (कुछ गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिसको परिमार्जन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाया हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकारों की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अध्यापक)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रस्ताव वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
1.	शामतारा	निरंक	निरंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी वन भूमि एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का होना पूर्ण था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि समुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/09/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17/09/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन को लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक/8 11 2022



ग्राम (डॉ. विष्णुका शुक्ला)
कलेक्टर एवं

ग्रामसभा-जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

18/11/2022

-प्रमाण पत्र-

प्रदर्शक

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कांकेर के द्वारा गैरयानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला के वन मंडल कांकेर के ग्राम आछीडोंगरी में स्थित वनभूमि आरएफ. 153 रकबा 2.9270 हे. कुल प्रस्तावित रकबा 2.9270 हे. भूमि है जिन्हे नवीन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.9270 हे. एवं राजस्व वन भूमि निरंक है. कुल भूमि 2.9270 हेक्टेयर जो ग्राम आछीडोंगरी में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा ग्राम आछीडोंगरी तहसील सरोना में स्थित है. तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 15/09/2022 (प्रदर्शक-"ब") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर दर्जित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत बिहावापारा में ग्राम सभा आछीडोंगरी के अध्यक्ष श्री राम मुरकाम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15/09/2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना को कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकारों की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

(अभ्या)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रस्तावित वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
		निरंक	निरंक
1.	आछीडोंगरी		

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी घर्षा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/09/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 15/09/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक 18/11/2022



ग्राम (डॉ. विद्याका शुक्ला)
कलेक्टर एवं
अभ्या-जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

116
18-11-2022

-: प्रमाण पत्र :-

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कांकर के द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु कांकर जिला के वन मंडल कांकर के ग्राम साल्हेटोला में स्थित नवीन वनभूमि ओए. 427 रकबा 2.1028 हे. कुल प्रस्तावित रकबा 2.1028 हे. भूमि है जिन्हे नवीन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.1028 हे. एवं राजस्व वन भूमि निरंक है. कुल भूमि 2.1028 हेक्टेयर जो ग्राम साल्हेटोला में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा ग्राम साल्हेटोला तहसील सरोना में स्थित है, तदनुसार यह कार्रवाई पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/09/2022 (प्रदर्श-"ब") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सारवण्डी में ग्राम सभा साल्हेटोला के अध्यक्ष श्री मनीराम भास्कर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/09/2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यून एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से संमझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अध्या)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या पामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0मे)
1.	साल्हेटोला	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी मर्चा एवं निर्णय लिखे गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/09/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17/09/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

दिनांक 18 / 11 / 2022



ग्राम (श्री. विष्णुका शुक्ला)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला चतार बस्तर कांकर

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कांकेर के द्वारा गैरयानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला के वन मंडल कांकेर के ग्राम बासनवाही में स्थित वनभूमि आरएफ. 127 रकबा 9.2590 हेक्टेयर एवं आरएफ. 128 रकबा 9.3693 हे. कुल प्रस्तावित रकबा 18.6283 हे. भूमि है जिन्हे नवीन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 18.6283 हे. एवं राजस्व वन भूमि निरंक हे. कुल भूमि 18.6283 हेक्टेयर जो ग्राम बासनवाही में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की जाती है, तथा ग्राम बासनवाही तहसील सरोना में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें प्रारित प्रस्ताव दिनांक 19/09/2022 (प्रदर्श-"ब") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम प्रधान बासनवाही में ग्राम सभा बासनवाही के अध्यक्ष श्री गांडाशम की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19/09/2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण वें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिसको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
1.	बासनवाही	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी धर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/09/2022 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (b) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 19/09/2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक 18/11/2022



नाम (श्री. प्रकाश शुक्ला)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला प्रस्ताव वस्तर कांकेर

Comments of Wildlife Institute of India on the proposed animal passage plan as part of Raipur-Vishakhapatnam greenfield highway (Ch. 0.000 – Ch. 124.661) in the state of Chhattisgarh under Bharatmala Parlyojana

Reference: 72nd meeting of the Standing Committee of NBWL, MoM – 72.4.33 (Page 60-61)

Background:

The forested landscape in Central India represents a mosaic of protected areas and multiple use zones. Presence of source population such as Tadoba Andhari Tiger Reserve, holds the lifeline for recovery of tiger population in a much larger connected landscape that includes tiger reserves such as Navegaon-Nagzira, Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi (Figure 1); Kanger Valley National Park and wildlife sanctuaries such as Chaprala, Pamed, Bhairamgarh and Sunabeda. Outside these protected areas, managed forests of Gadchiroli, Bilapur, Dantewada, North Bastar, Kondagaon, Keshkal and Kanker provide forest connectivity. Maintaining the integrity of this landscape is of utmost importance for future recovery of tiger population in the above-mentioned protected areas as well as managed forests.

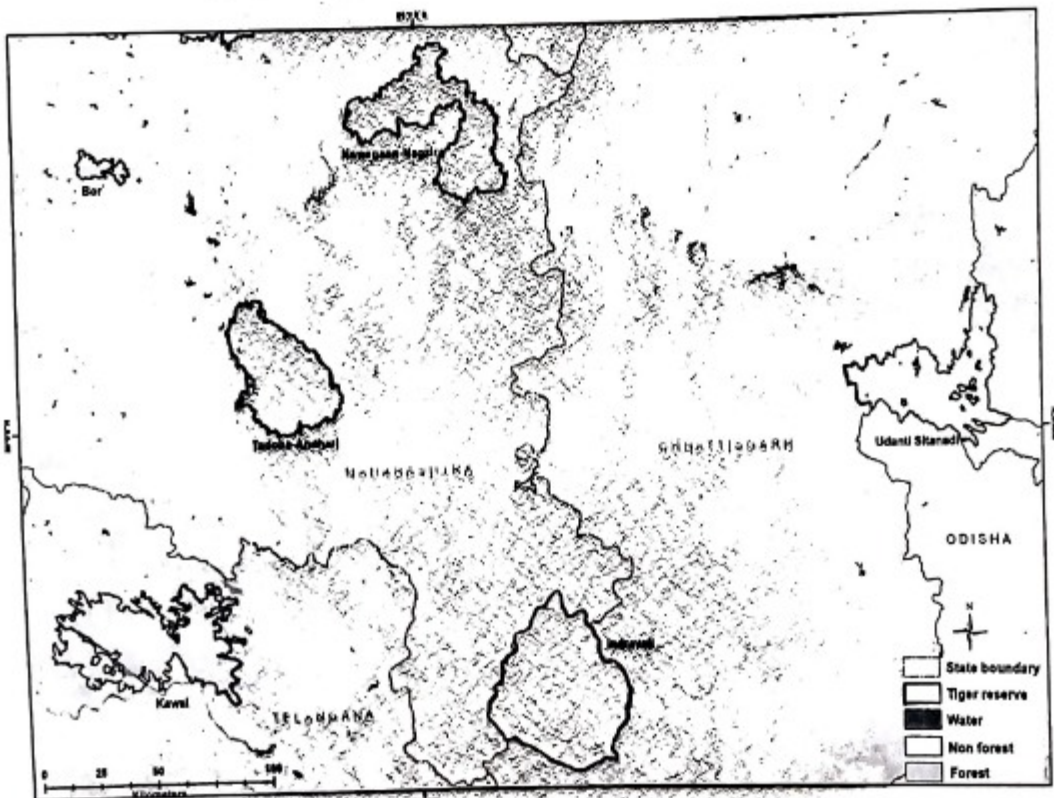
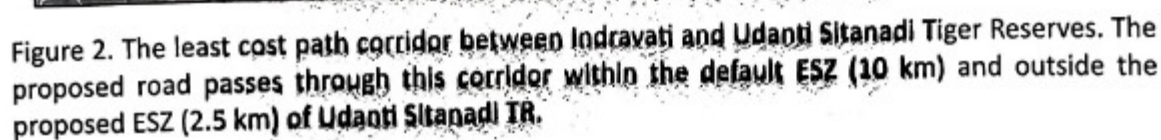


Figure 1. Thriving tiger population in Tadoba Andhari TR acts as a major lifeline for recovery of tiger population in other reserves such as Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi in Central India that still maintain forest connectivity.

The proposed road in the context of tiger reserves in Central India. Two stretches of proposed alignment of the green field economic corridor, Raipur Vishakhapatnam under Bharatmala Pariyojana (NH130 CD) passes through the deemed ESZ boundary of 10 km of Udanti Sitanadi Tiger Reserve. The project alignment is outside the draft ESZ of 2.5 km proposed by the Government of Chhattisgarh. However, the project alignment intersects near chainage 104.900 to chainage 108.350 for a distance of 3.45 km, the tiger dispersal corridor between Indravati Tiger Reserve-Udanti Sitanadi Tiger Reserve and Sunabeda Wildlife Sanctuary delineated by NTCA and WII in 2014 (Fig. 2).



The user agency has proposed three viaducts of length 300m at ch. 104.210 to 104.510; 300 m at ch. 105.719 to 106.019; 360 m at 106.260 to 106.620 and a twin tube tunnel of 2.79 km from ch. 106.820 to 109.610 (Fig. 3). The height of these viaducts varies from a minimum of 6m to a maximum of 8m, thus providing adequate scope for movement of large herbivores like elephants using this landscape.

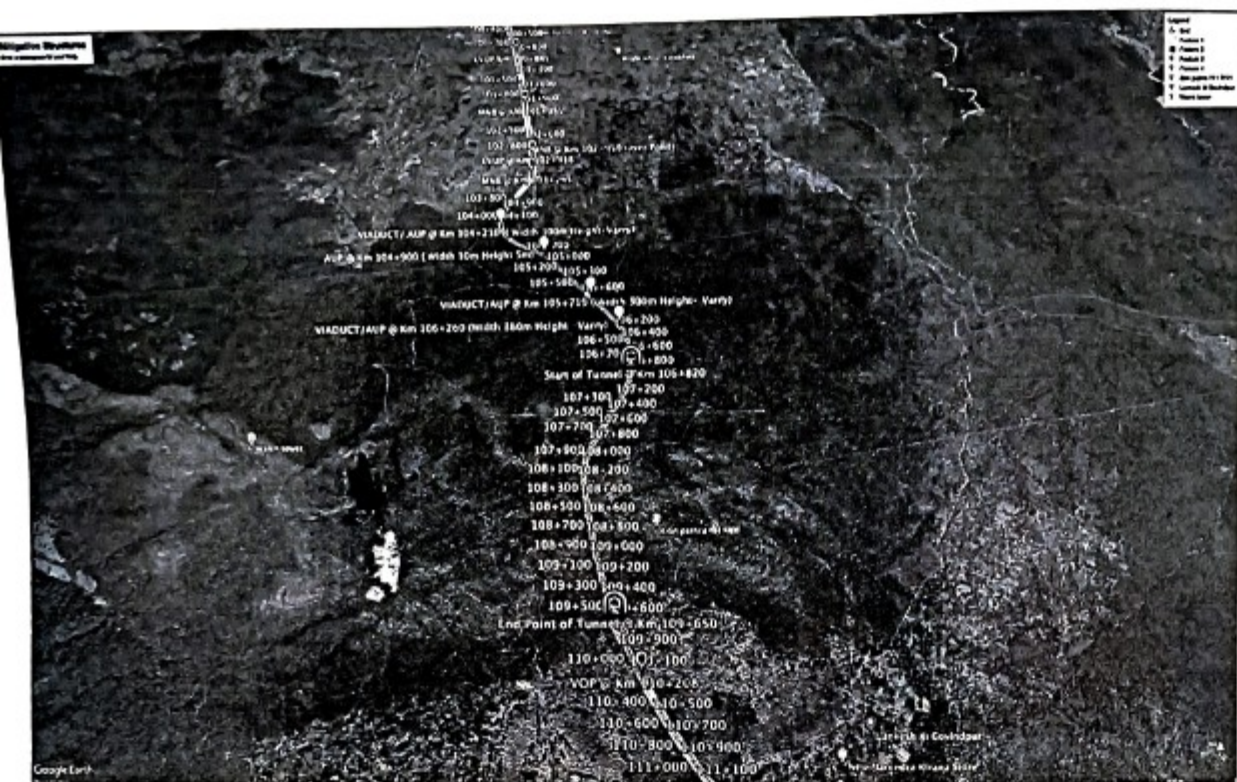


Figure 3. A total of three via ducts spanning over 960m and a twin tube tunnel of 2.79 km are the proposed mitigation measures by the project proponent.

Observations based on the site inspection;

A site inspection was carried out by Dr. Bivash Panday, Scientist G of WII on 12 and 13 June 2023. Following a detailed discussion with the engineers of NHAI, all the locations where the three viaducts and the twin tube tunnel are proposed were visited. The site selection of mitigation measures are appropriate. The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km. The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision with wild animals.



F.No.WL-6/20/2023-WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wild Life Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, New Delhi-110003.

Date: 11th May, 2023

To
All Members
Standing Committee of NBWL

Sub: Minutes of 72nd Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life-reg.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed copy of the Minutes of 72nd Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on 25th April, 2023 under the chairmanship of Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

SUDHEER
CHINTALAPATI

Yours faithfully

Digitally signed by SUDHEER
CHINTALAPATI
Date: 2023.05.11 12:33:35 +05'30'

(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in.

Encl: As above

Distribution:

1. Secretary, MoEF & CC
2. DGF&SS, MoEF&CC.
3. ADGF(WL), MoEF&CC.
4. ADGF(FC), MoEF&CC.
5. Member Secretary, NTCA.
6. Director/IGF, PE Division, MoEF&CC.
7. Director, WII, Dehradun.
8. Director, GEER Foundation, Gandhinagar.
9. Dr. R. Sukumar, Member, NBWL.
10. Dr. H.S. Singh, Member, NBWL.
11. Secretary, Environment, Forest, Science and Technology Department, Govt. of Andhra Pradesh.

Copy to:

1. PS to Hon'ble MoEF&CC.
2. PS to Hon'ble MoS, EF&CC.
3. PPS to Secretary, MoEF & CC
4. PPS to DGF&SS, MoEF&CC.

The Standing Committee was informed that the proposal is for Bangalore-Chennai Expressway Phase-II-Wildlife for Non-Forest stretch falling within ESZ of Kaundinya Wildlife Sanctuary in Chittoor District in the state of Andhra Pradesh.

The proposal has been recommended by Chief Wild Life Warden, State Board for Wild Life and State Government.

Decision Taken: After discussion, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The proposed area will be utilized only for the purpose for which the user agency has sought, but not for any other commercial purpose.
2. The User Agency should inform the commencement of the work to the Concerned DFO. The diversion work will be executed under the supervision of the Forest Department.
3. The User Agency should invariably demarcate the proposed land for diversion with any suitable permanent stones/pillars. After demarcation only the works should be commenced.
4. The User Agency should not resort to the excavation of the surrounding forest land for collection of the earth to be used. If such excavation is found during the work period or later, the User Agency will be charged with suitable provisions of relevant acts.
5. The User Agency shall obey any other conditions stipulated by the Forest Department as per Acts and Rules.
6. The User Agency will be solely responsible for every violation which attracts the provisions of A.P Forest Act and Forest Conservation Act, 1980.
7. Wildlife Conservation plan for Rs.1698.00 lakhs to be deposited by the User Agency in Wildlife Conservation Projects & CSP (WLC & CSR).
8. The User Agency shall deposit 2% of project cost in BIOSAT account for conservation of the elephant habitat to tackle the Human and Elephant conflicts and Mitigation other ameliorative measures.
9. Wildlife signage boards to be erected in and around the entire project.
10. Work shall be carried out only from dawn to dusk.
11. No labour camps to be established in the protected area.

72.4.33

Proposal for use of 198,3084 of forest land from Udanti-Sitanadi Tiger Reserve for development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under BharatmalaPariyojana.
FP/CG/ROAD/119866/2021

The Standing committee was informed that the proposal is for use of 198.3084 of forest land from Udanti-Sitanadi Tiger Reserve for development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana.

The proposal has been recommended by Chief Wild Life Warden, State Board for Wild Life and State Government.

Dr Sukumar said that the area has wild buffaloes and the user agency must take all necessary steps to provide safe passage for wild animals.

Dr. H. S Singh said that since these highways are meant for movement of high speed vehicles, the animal passage plan should to re-examined.

Decision Taken: After discussion, the standing committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The animal passage plan needs to be examined by the WII.
2. The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only.
3. Any other condition imposed from time to time by forest department.
4. There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.
5. All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals.
6. Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.
7. There will not be a right of passage to the public via the underpass.
8. The CWLW should have an adequate monitoring mechanism in place.

72.4.34

Proposal for use of 1.3105 ha of forest land from Amrabad Tiger Reserve for laying of QEC along the road within the existing RoW for execution of T-Fiber Project in Nagarjunasagar division of Nalgonda District in favour of Telangana Fiber Grid Corporation Limited.
FP/TG/QFC/142849/2021.

Comments of Wildlife Institute of India on the proposed animal passage plan as part of Raipur-Vishakhapatnam greenfield highway (Ch. 0.000 – Ch. 124.661) in the state of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana

Reference: 72nd meeting of the Standing Committee of NBWL, MoM – 72.4.33 (Page 60-61)

Background:

The forested landscape in Central India represents a mosaic of protected areas and multiple use zones. Presence of source population such as Tadoba Andhari Tiger Reserve, holds the lifeline for recovery of tiger population in a much larger connected landscape that includes tiger reserves such as Navegaon-Nagzira, Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi (Figure 1); Kanger Valley National Park and wildlife sanctuaries such as Chaprala, Pamed, Bhairamgarh and Sunabeda. Outside these protected areas, managed forests of Gadchiroli, Bilapur, Dantewada, North Bastar, Kondagaon, Keshkal and Kanker provide forest connectivity. Maintaining the integrity of this landscape is of utmost importance for future recovery of tiger population in the above-mentioned protected areas as well as managed forests.

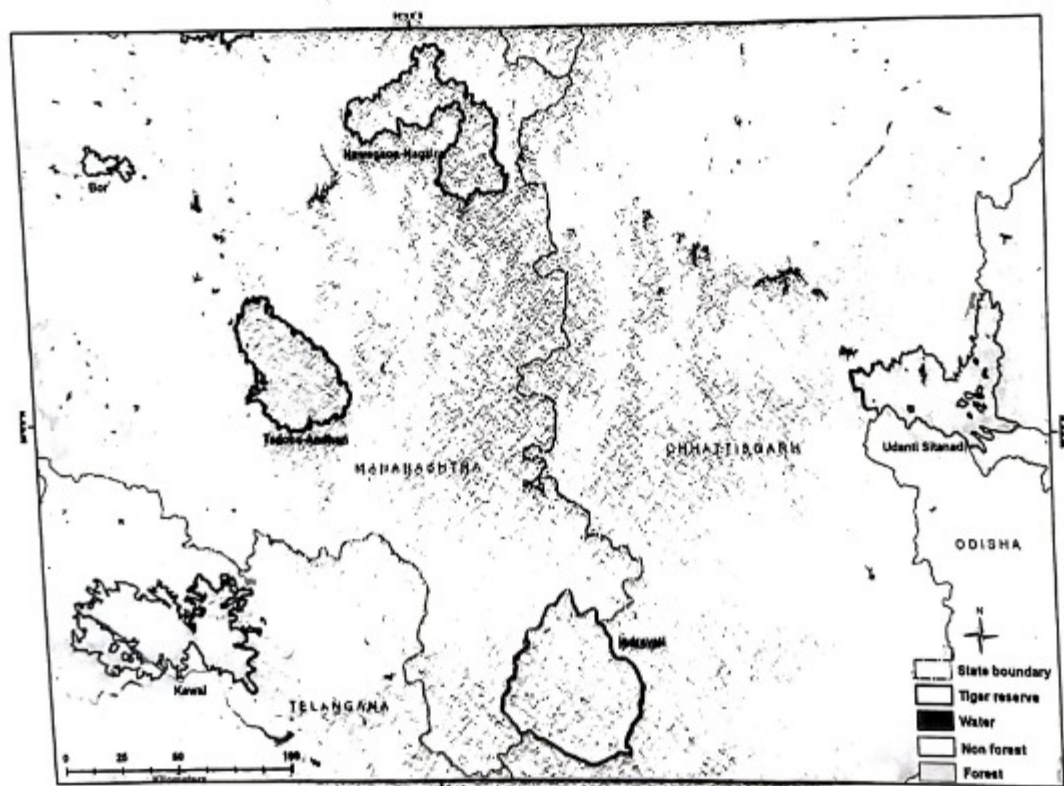


Figure 1. Thriving tiger population in Tadoba Andhari TR acts as a major lifeline for recovery of tiger population in other reserves such as Kawal, Indravati and Udanti Sitanadi in Central India that still maintain forest connectivity.

The proposed road in the context of tiger reserves in Central India:

Two stretches of proposed alignment of the green field economic corridor, Raipur Vishakhapatnam under Bharatmala Pariyojana (NH130 CD) passes through the deemed ESZ boundary of 10 km of Udanti Sitanadi Tiger Reserve. The project alignment is outside the draft ESZ of 2.5 km proposed by the Government of Chhattisgarh. However, the project alignment intersects near chainage 104,900 to chainage 108,350 for a distance of 3.45 km, the tiger dispersal corridor between Indravati Tiger Reserve-Udanti Sitanadi Tiger Reserve and Sunabeda Wildlife Sanctuary delineated by NTCA and WII in 2014 (Fig. 2).

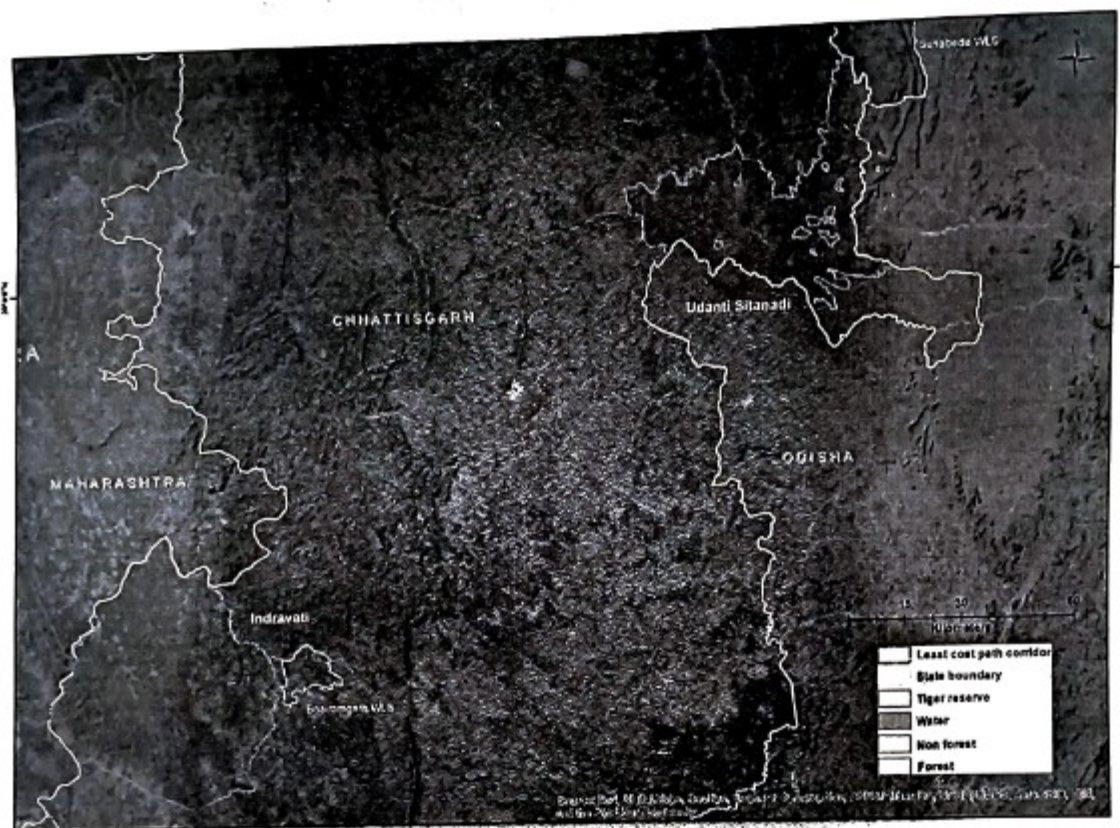


Figure 2. The least cost path corridor between Indravati and Udanti Sitanadi Tiger Reserves. The proposed road passes through this corridor within the default ESZ (10 km) and outside the proposed ESZ (2.5 km) of Udanti Sitanadi TR.

Proposed mitigation measures in the corridor:

The user agency has proposed three viaducts of length 300m at ch. 104.210 to 104.510; 300 m at ch. 105.719 to 106.019; 360 m at 106.260 to 106.620 and a twin tube tunnel of 2.79 km from ch. 106.820 to 109.610 (Fig. 3). The height of these viaducts varies from a minimum of 6m to a maximum of 8m, thus providing adequate scope for movement of large herbivores like elephants using this landscape.



Figure 3. A total of three via ducts spanning over 960m and a twin tube tunnel of 2.79 km are the proposed mitigation measures by the project proponent.

Observations based on the site inspection:

A site inspection was carried out by Dr. Bivash Panday, Scientist G of WII on 12 and 13 June 2023. Following a detailed discussion with the engineers of NHAI, all the locations where the three viaducts and the twin tube tunnel are proposed were visited. The site selection of mitigation measures are appropriate. The extent and structural design of the proposed mitigation measures are adequate. The mitigation measures proposed effectively covers a distance of 3.79 km in a forest patch of 6.54 km. The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision with wild animals.